



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 20, 2016/आश्विन 28, 1938

No. 336]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 20, 2016/ASVINA 28, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2016

प्रारंभिक जाँच परिणाम

विषय : चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अलाय या गैर-अलाय स्टील के कलर कोटेड/प्री-पेंटेड फ्लैट उत्पाद" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी प्रारंभिक जाँच परिणाम के संबंध में

सं. 14/28/2016-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

2. मैसर्स एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड और मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कंपनियां या आवेदक भी कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से "अलाय या गैर-अलाय स्टील के कलर कोटेड/प्री-पेंटेड फ्लैट उत्पाद" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के कथित पाटित आयातों पर पाटनरोधी जाँच की शुरुआत और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

3. और यतः प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29.06.2016 की अधिसूचना सं. 14/28/2016-डीजीएडी द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें पाटनरोधी नियमावली के अनुसार

संबद्ध जाँच की शुरुआत की गई ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।

क प्रक्रिया

4. नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- (i) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उपनियम (5) 5 के अनुसार जाँच की कार्यवाही की शुरुआत करने से पहले आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में ईयू का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय यूरोपीय संघ के शिष्टमंडल और चीन जन. गण. के दूतावास को अधिसूचित किया।
- (ii) प्राधिकारी ने भारत में स्थित यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों और चीन जन. गण. के दूतावास, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गये पतों अनुसार संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध वस्तु के आयातकों/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों को जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार उनसे जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- (iii) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुरूप आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति भारत में भारत में स्थित यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों और चीन जन. गण. के दूतावास, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों को भेजी थी। आवेदन की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षों को भी भेजी गई थी।
- (iv) भारत में स्थित यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों और चीन जन. गण. के दूतावास से उनके देशों के उत्पादकों/निर्यातकों को विहित समय-सीमा के भीतर उनके उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह देने का भी अनुरोध किया गया था।
- (v) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए उन्हें निर्यातक प्रश्नावलियां भेजीं:

यूरोपीय संघ (ई यू)

1. स्टील कोट अल्यूर (आर्सिलर मित्तल)
2. थाइसेन कुरुप स्टील यूरोप ए जी
3. टाटा कोरस
4. एस एस ए बी
5. मेटल ट्रेड कोमैक्स
6. वोएस्टालपाइन ए जी

चीन जन. गण.

1. संघाई मेटल कारपोरेशन
2. बाओस्टील ग्रुप कारपोरेशन
3. साइनो इस्ट स्टील इंटरप्राइजेज कं. लि.
4. किंगदाओ साइनो स्टील कंपनी लि.
5. संघाई कलर स्टील कंपनी लि.

- (vi) जाँच शुरू करने संबंधी अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों से निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों और व्यापारियों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है:

चीन जन. गण.

- (i) शांगफोन ह्वाफोन स्टील कंपनी लि. (उत्पादक)
- (ii) जियांगशू शागांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लि. (निर्यातक)
- (iii) झांगजियांग शाजिंग ह्वी प्लेट कंपनी लि. (उत्पादक)
- (iv) शागांग इंटरनेशनल सिंगापुर प्रा. लि. (निर्यातक)
- (v) किंगदाओ आरएचटी स्टील कं. लि. (निर्यातक)

- (vi) मैसर्स जियांगिन जिंगचेंग स्पेशल स्टील वर्क्स कंपनी लि. (उत्पादक/ निर्यात)
- (vii) चीन जन. गण. से किसी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जॉच में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का खंडन करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) का दावा नहीं किया है।
- (viii) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:
1. सनग्रीन वेंटिलेशन सिस्टम्स (प्रा.) लिमिटेड
 2. श्री रामा स्टील सिंडिकेट,
 3. इंडियन पाइप्स प्रा. लि.
 4. मैटल साइन रुफिंग ,
 5. वृजलाल एंड संस
 6. कुमार कारपोरेशन
 7. ओरियंटल मैटल्स इंडिया प्रा. लि.
 8. एम के कम मैटल सैक्सन्स प्रा. लि.
 9. कुसम मैटल्स प्रा. लि.
 10. स्टील कंपनी
 11. शंकर मरकेटाइल प्रा. लि.
 12. जी एम ट्रेडर्स
 13. पी बी ट्रेडर्स प्रा. लि.
 14. व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड
 15. सेमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
- (ix) व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक/ उपयोक्ता ने प्रश्नावली उत्तर के रूप में उत्तर नहीं दिया है अथवा जांच शुरुआत करने के लिए कोई टिप्पणी प्रदान नहीं की है।
- (x) इसके अलावा निम्नलिखित पक्षों ने जॉच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के संबंध में अनुरोध/टिप्पणियों प्रस्तुत की हैं।
1. भारत में स्थित यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि
 2. व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड
 3. मैसर्स जियांगिन जिंगचेंग स्पेशल स्टील वर्क्स कंपनी लि. , चीन जन. गण.
 4. चाइना चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल कामर्स
- (xi) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच हेतु रखी गई सार्वजनिक फाईल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया गया। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों पर वर्तमान जॉच परिणाम में ध्यान दिया गया है।
- (xii) गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।
- (xiii) आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षों से आवश्यक समझी गई सीमा तक और सूचना मांगी गई थी।
- (xiv) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्ष ने न तो प्राधिकारी को उत्तर दिया है और न ही वर्तमान जॉच के दौरान आवश्यक सूचना प्रस्तुत की है या जॉच में काफी बाधा डाली है, उन्हें प्राधिकारी द्वारा असहयोगी हितबद्ध पक्ष माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जॉच परिणामों को रिकार्ड किया है।
- (xv) घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों) जीएएपी (के आधार पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने तथा उसकी बिक्री करने की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी कहा गया है) का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार किया जिससे कि यह निर्धारित

- किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (xvi) इस तथ्य पर विचार करते हुए कि संबद्ध वस्तु का आयात विभिन्न ग्रेडों/आकारों/आयामों में किया जा रहा है, आवेदकों ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना के लिए पीसीएन से पीसीएन की तुलना करने के लिए उत्पाद नियंत्रण सं. (पीसीएन) का भी प्रस्ताव किया है। तथापि प्रारंभिक जाँच परिणामों के लिए प्राधिकारी ने पीसीएन से पीसीएन का तुलना को नहीं अपनाया है।
- (xvii) आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के संबंध में आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था। आवश्यक सुधार के साथ केवल ऐसी सत्यापित सूचना जहां लागू हो, पर वर्तमान प्रारंभिक जाँच परिणामों के प्रयोजनार्थ भरोसा किया गया है।
- (xviii) यह जांच 1 जुलाई, 2015 से प्रारंभ करके 31 दिसम्बर, 2015 (6 महीने) (जिसे आगे 'जाँच अवधि' या पीओआई भी कहा गया है) तक की गई है। तथापि, क्षति विश्लेषण के लिए प्रवृत्तियों की जाँच में वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15, अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 और जांच की अवधि को शामिल किया गया।
- (xix) याचिकाकर्ताओं ने आईबीआईएस से प्राप्त सौदावार आयात आकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है। तथापि, जाँच की शुरुआत के बाद केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) से जाँच अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदावार ब्योरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्रारंभिक जाँच परिणाम में प्राधिकारी ने डेटा प्रबंधन निदेशालय, सीबीईसी, के आकड़ों पर भरोसा किया है।
- (xx) जाँच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों और सूचना पर साक्ष्यों से समर्थित होने और वर्तमान जाँच से संगत होने पर विचार किया गया और प्रारंभिक जाँच परिणाम पर प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से ध्यान दिया गया है।
- (xxi) सीमाशुल्क आकड़ों के अनुसार पीओआई के लिए अमरीकी डालर से भारतीय रुपये में परिवर्तन की विनिमय दर को 65.93 भारतीय रुपये माना गया है।
- (xxii) इस अधिसूचना में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

- वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद प्री पेंटेड, पेंटेड, कलर कोटेड और कार्बनिक कोटेड काइलों या काइलों में नहीं फ्लैट स्टील हैं चाहे जिक, अल्युमिनियम जिक या किसी अन्य सबस्ट्रेट कोटिंग के साथ हो। ये स्टील या तो अलाय या नॉन अलाय स्टील के होते हैं चाहे प्राइम या गैर-प्राइम गुणवत्ता के हों काइलों या प्लेन शीटों या प्रोफाइल शीटों में जिनमें ट्रेपेजोइडल, सिनुसोइडल, नालीदार या किसी अन्य प्रकार की प्रोफाइल हो। ये उत्पाद विभिन्न पेंट गुणवत्ताओं और अनेक पेंट रंगों में उपलब्ध हैं चाहे प्राइमर या किसी अन्य उपयुक्त सामग्री से से प्री-कोटेड हों। ये स्टील या तो स्टील शीट की ऊपरी सतह पर या निचली सतह पर या ऊपरी और निचली दोनों सतहों पर पेंटेड हो सकते हैं। इस उत्पाद को गार्ड फिल्म/लेमिनेशन के साथ या उसके बिना आपूर्ति किया जा सकता है।
- विचाराधीन उत्पाद में बैरियर संरक्षण के साथ जंग का भी प्रतिरोध होता है। पीयूसी को अनेक अनुप्रयोगों और क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है जिनमें शामिल हैं निर्माण, रूफिंग, वालिंग, पैनलिंग, क्लेडिंग और डेकिंग, आटोमोटिव, व्हाइट गुड्स और उपकरण एवं फर्नीचर आदि परंतु यह इन तक सीमित नहीं है।
- विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की टैरिफ मद 72107000, 72124000, 72259900 और 72269990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि कतिपय अन्य आईटीसी एचएस कोडों अर्थात् 72101110, 72101190, 72101210, 72101290, 72103010, 72103090, 72104100, 72104900, 72105000, 72106100, 72106900, 72109010, 72109090, 72121010, 72121090, 72122090, 72123090, 72125020, 72125090, 72126000, 72255030, 72259200 और 72261100 के अंतर्गत भी आयात हुए हैं। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों के अनुरोध

- विचाराधीन उत्पाद से संबंधित मुद्दों के संबंध में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- (i). पाटन और क्षति गणना में विभिन्न प्रकार के उत्पादों एवं गुणवत्ताओं को ध्यान में रखा गया है।
- (ii). एक निर्यातक ने यह अनुरोध किया है कि उन्होंने भारत को मध्यम अथवा भारी प्लेट का निर्यात किया है जिसकी मोटाई 6 एम एम या अधिक की है जिसे एक प्रकार के शॉप प्राइमर से पेंट किया गया है। यह उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आता लेकिन तब भी उन्होंने पूर्ण सावधानी बरतते हुए निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। विचाराधीन उत्पाद के अनुप्रयोगों और निर्यातक द्वारा निर्यातित उत्पाद के अनुप्रयोगों में अंतर है। सामान्यतः विचाराधीन उत्पाद की मोटाई 6 एम एम से कम है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

9. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गये अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- (i) घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद में सभी कोटेड उत्पाद शामिल हैं, चाहे प्री-पेंटेड, पेंटेड, कलर कोटेड या आर्गेनिक कोटेड फ्लेट स्टील कॉइल हो, जो चाहे मैटलिक कोटेड जिक सव्सट्रेट हो, एल्यूमिनियम जिक हो या नहीं अथवा कोई और सव्सट्रेट कोटिंग हो। ये स्टील या तो अलॉय या नॉन अलॉय स्टील हो, जो चाहे प्राइम क्वालिटी हो या नान प्राइम क्वालिटी हो, चाहे कॉइल के रूप में हो या प्लेन शीट के रूप में या प्रोफाइल शीट के रूप में हो जिसमें ट्रेपजोइडल, साइनूसाइडल, कोरुगेटेड या किसी अन्य प्रकार की प्रोफाइल शामिल है लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- ii) निर्यातक के अनुरोध के संबंध में कि 6 एम एम या अधिक की मोटाई वाली भारी प्लेटों को जांच के दायरे से बाहर रखा जाए, घरेलू उद्योग का यह कहना है कि इस तर्क को स्वीकार किया जाए क्योंकि ये प्लेटें पहले से ही जांच के दायरे के भीतर शामिल नहीं की गई हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- 10. हितवद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद से संबंधित मामलों के संबंध में किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए अनुरोधों की जांच की गई है और यह पाया गया है कि:
 - (i) घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद में ऐसे स्टील जो अलॉय हो या नॉन अलॉय स्टील हो, जो चाहे प्राइम क्वालिटी हो या नान प्राइम क्वालिटी हो, चाहे कॉइल के रूप में हो या प्लेन शीट के रूप में या प्रोफाइल शीट के रूप में हो जिसमें ट्रेपजोइडल, साइनूसाइडल, कोरुगेटेड या किसी अन्य प्रकार की प्रोफाइल शामिल है लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है। तदनुसार विचाराधीन उत्पाद में 6 एम एम या उससे अधिक की मोटाई वाली प्लेटें शामिल नहीं हैं। चूंकि यह उत्पाद विचाराधीन जांच के दायरे में नहीं आता इसलिए इस उत्पाद के लिए कोई विशेष निष्कासन प्रदान किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
 - (ii) समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में यह प्रावधान है कि: "समान वस्तु" से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है, जो भारत में पाटित किए जाने के लिए की जा रही जांच के अधीन वस्तु के समान अथवा एक जैसी है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर कोई अन्य वस्तु, जो यद्यपि पूरी तरह से समान तो नहीं है, लेकिन जांच की जा रही वस्तु से काफी मिलती-जुलती विशेषताओं वाली है। उपलब्ध सूचना के आधार पर और हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से यह पाया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों ही भौतिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रियाओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों ही तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापित करने योग्य हैं। उपभोक्ता दोनों को ही एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग में लाते हैं। प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से यह पाया है कि वे आवेदकों द्वारा निर्मित उत्पाद संबद्ध देशों से भारत में आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तुएं हैं।

ग. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

- 11. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा।"

12. मै. एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड और मै. जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड उपरोक्त उत्पादकों के उत्पादन में कुल घरेलू उद्योग का एक बड़ा हिस्सा शामिल है और वह भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक है।

विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

13. भारतीय उत्पादकों द्वारा याचिका के लिए समर्थन की गणना और उसका आधार स्पष्ट नहीं है और इन गणनाओं के लिए जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, वे हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाएं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

14. इस मामले के संबंध में कि याचिका के समर्थन की गणना और आधार स्पष्ट नहीं है इसलिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह याचिका मैसर्स एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड और मैसर्स जे एस डब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट लिमिटेड द्वारा दाखिल की गई है तथा इन उत्पादकों का कुल घरेलू उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा होता है। इन उत्पादकों का हिस्सा भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक है, जैसा कि नीचे सारणी से देखा जा सकता है। इसके अलावा वर्तमान आवेदन का कोई समर्थक नहीं है।

उत्पादन	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 15- दिसंबर 15 (क)	जांच की अवधि (जुलाई 15- दिसंबर 15)	जांच की अवधि (क)
याचिकाकर्ता							
-एस्सार स्टील इंडिया लि.	मी. टन	179,284	200,914	140,056	169,537	79,073	158,146
- जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लि.	मी. टन	234,715	373,875	417,440	421,848	197,345	394,689
याचिकाकर्ता का कुल उत्पादन	मी. टन	413,999	574,789	557,496	591,385	276,418	552,835
अन्य का उत्पादन	मी. टन	408,001	305,211	350,504	320,615	161,582	323,165
कुल घरेलू उत्पादन (जेपीसी डाटा के आधार पर)	मी. टन	822,000	880,000	908,000	912,000	438,000	876,000

15. अतः प्राधिकारी ने यह पाया कि आवेदकों का भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के बड़े हिस्से पर कब्जा है और इस जांच के प्रयोजन से आवेदक नियम 5(3) के संदर्भ में स्थायी जरूरतों को पूरा करता है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है।

घ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विविध मामले

16. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विविध अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा जिन्हें संगत समझा गया है, वे इस प्रकार हैं:

- जांच की अवधि "प्रतिनिधित्व के रूप में और यथा संभव शीघ्र" होनी चाहिए। एक वर्ष की जांच की अवधि के बेंचमार्क से विचलन और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से प्रमाणित और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से प्रमाणित सकारात्मक साक्ष्य देने होंगे, जो वर्तमान मामले में मौजूद नहीं है। छः माह की जांच की अवधि किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए काफी कम है और यह कम से कम एक वर्ष होनी चाहिए।
- याचिका में प्रदान की गई सूचना जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है और कतिपय आंकड़े गलत ढंग से गोपनीय माने गए हैं। गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप विस्तार से नहीं है।

(ii) घरेलू उद्योग को पहले ही विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) करारों के उल्लंघन के लिए कई संरक्षण प्राप्त हैं :

- सीमा शुल्कों में वृद्धि
- न्यूनतम आयात कीमत
- अन्य स्टील उत्पादों पर पाटन रोधी जांच

(iii) आयात संबंधी आंकड़े हितबद्ध पक्षकारों को एम एस एक्सल फार्म में प्रदान किए जाएंगे।

(iv) संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को ही अनुचित लाभ होगा न कि यह घरेलू उद्योग के व्यापक हित में होगा।

17. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विविध अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा जिन्हें संगत समझा गया है, वे इस प्रकार हैं:

- (i) अधिनियम की धारा 9 क(3) उत्पाद के पाटन के इतिहास के संदर्भ में है। याचिकाकर्ता प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाने की सिफारिश करें क्योंकि पूर्वव्यापी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगाने की शर्त पूरी है।
- (ii) संबद्ध वस्तुओं के पाटन के साक्ष्य हैं, जो इस तथ्य से स्पष्ट हैं कि कनाडा, यूएस, टर्की, यूरोपीय संघ इत्यादि सहित कई देशों ने स्टील के होट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। अपेक्षाकृत कम समय में भारत में विचाराधीन उत्पाद का भारी मात्रा में पाटन हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- (iii) निर्यातकों को अच्छी तरह से इस बात की जानकारी है कि वे पाटन का सहारा ले रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतें काफी कम हुई हैं, जैसा कि संबंधित देशों के लिए लदान मूल्य से स्पष्ट है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

18. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा जिन्हें संगत समझा गया है, उनकी जांच की गई है और यह पाया गया है कि:

- (i) हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि जांच की अवधि 6 माह से अधिक होनी चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी प्रक्रियाओं संबंधी समिति की सिफारिश (डब्ल्यूटीओ दस्तावेज संख्या जी/एडीपी/6 दिनांक 16 मई, 2000) के अनुसार;

"..... पाटन जांच के लिए डाटा संकलन की अवधि सामान्यतः बारह माह होनी चाहिए और किसी भी रूप में जांच की शुरुआत की तारीख से व्यावहारिक दृष्टि से निकटतम छः माह से कम की नहीं होनी चाहिए।"

अतः उपरोक्त सिफारिश को देखते हुए 6 माह की अवधि को जांच की अवधि के रूप में लिया जा सकता है। प्राधिकारी ने अन्य जांचों में भी 6 माह की जांच की अवधि को लिया है।

- (ii) इस मामले के संबंध में कि घरेलू उद्योग को विश्व व्यापार संगठन करारों (डब्ल्यू टी ओ) के उल्लंघन में कई संरक्षण पहले से ही प्राप्त हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसे केवल पाटनरोधी नियमावली के तहत विनिर्दिष्ट स्थिति की ही जांच करनी है। अन्य स्टील उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क की प्रयोज्यता का अर्थ यह नहीं है कि घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
- (iii) संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा पेश की गई कम कीमतों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा एमआईपी शुरु की गई थी। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि 4 दिसंबर, 2016 तक एमआईपी लागू है। एमआईपी समाप्त हो जाने पर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से कोई संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसके अलावा एमआईपी की मौजूदगी का अर्थ यह नहीं है कि पाटन नहीं हो रहा है।
- (iv) इस संबंध में कि आयात के आंकड़े एम एस एक्सल फार्मेट में उपलब्ध कराए जाने चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदकों द्वारा जिन आयात आंकड़ों पर भरोसा किया गया है वे आवेदन के अगोपनीय अंश में प्रदान किए गए हैं। पाटनरोधी नियमावली के तहत एम एस एक्सल फार्मेट में आयात के डाटा उपलब्ध कराने की कोई अपेक्षा नहीं है।
- (v) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह तर्क कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग को अनुचित फायदा होगा, यह पूर्वानुमान और असामयिक है। पाटनरोधी जांच तथ्यों और कानून पर आधारित होती है और पाटन की मात्रा तथा घरेलू उद्योग पर इसके परिणामस्वरूप होने वाले क्षतिकारी प्रभाव का विश्लेषण करने और आकलन करने के लिए तथा समुचित और पर्याप्त पाटनरोधी उपाय करने के लिए होती है ताकि घरेलू उद्योग को भी पाटन से मुकाबला करने के लिए मुकाबले में लाया जा सके।

- (vi) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को आवश्यकतानुसार स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान वाले पक्षकारों को यह निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करें। प्राधिकारी ने एक सार्वजनिक फाइल में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय अंश प्रदान किया है।
- (vii) जहां तक भूतलक्षी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगाने के अनुरोध का संबंध है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(3) में प्रावधान इस प्रकार है:

जांच के अधीन पाटित वस्तु के संबंध में यदि केंद्र सरकार का यह अभिमत है कि:

- (i) पाटन काफी पहले से किया जा रहा है, जिससे क्षति हुई है अथवा कि आयातक को यह ज्ञात था अथवा ज्ञात होना चाहिए था कि निर्यातक पाटन कर रहा है और यह कि ऐसे पाटन से क्षति पहुँचेगी, और
- (ii) अपेक्षाकृत लघु अवधि में आयातित किसी वस्तु के भारी मात्रा में पाटन से क्षति हुई है, जिससे पाटित आयातित वस्तु के समय और मात्रा एवं अन्य परिस्थितियों के मद्देनजर लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क का सुधारात्मक प्रभाव कम होने की संभावना है, तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से उप-धारा (2) के अंतर्गत भूतलक्षी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की तारीख से पहले की तारीख से पाटनरोधी शुल्क लगा सकती है परंतु इस उप-खंड के अंतर्गत शुल्क अधिरोपण की तारीख अधिसूचना की तारीख से नब्बे दिन पूर्व तक ही होगी और इस समय लागू किसी कानून में किसी बात के होते हुए भी ऐसे शुल्क का भुगतान उस दर एवं उस तारीख से किया जाएगा, जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो।
- (viii) प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम की अवस्था में पाटनरोधी शुल्क भूतलक्षी प्रभाव से लगाने से संबंधित मामले की जांच करेगी।
- (ix) वर्तमान जांच आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना/डाटा के प्रथम दृष्टया विश्लेषण के आधार पर शुरू की गई है, जिसमें कि संबंध देशों से संबंधित वस्तुओं के पाटन, इस पाटन के कारण आवेदक को क्षति और दोनों केंद्रीय कारणात्मक संबंध दर्शाया गया है। प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत भ्रामक आंकड़ों और प्राधिकारी द्वारा आंकड़ों के अनुचित मूल्यांकन के आधार पर जांच शुरू करना कानून के अनुसार गलत है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वह जांच की शुरुआत के समय याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर सूचना की सटीकता और पर्याप्तता के बारे में प्रथम दृष्टया स्वयं संतुष्ट हैं।

पाटन मार्जिन

बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य

19. धारा 9 क (1)(ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य:
- i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो, तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा
- (ख) उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्भूत वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

परंतु यह कि उद्गम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

गैर-व्यापार अर्थव्यवस्था वाले देशों के संबंध में प्रावधान:

20. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 में कहा गया है:

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकल्पित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”

8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ कि देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धांतों का लागू नहीं करने वाले के रूप में मानते हैं। जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं के विक्रयों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वानुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।

तथापि, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या:

(क) ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, विक्रयों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं;

(ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाए गए विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है। खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसंपत्तियों के ह्रास अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में;

(ग) ऐसी फर्म दिवालिया तथा संपत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्म के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है:-

(घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं:-

तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धांतों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के संबंध में किए गए विभिन्न अनुरोधों और जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत समझा गया है, उनकी जांच की गई है, जो नीचे दिए गए हैं:
- (i) सामान्य मूल्य का निर्माण उपयुक्त नहीं है। सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए प्रयुक्त की गई उत्पादन लागत कम क्षमता उपयोग के कारण बहुत ही अधिक है।
 - (ii) घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किए जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा निर्मित सामान्य मूल्य के आधार पर औसतन पाटन गणना भी इतनी सरल है और इसमें विभिन्न प्रकार के उत्पादों को नहीं दर्शाया गया है।

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

22. जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में प्रस्तुत किए गए विभिन्न अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा जिन्हें संगत समझा गया है, इस प्रकार हैं:
- (i) चीन का कोई भी उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे के बारे में संतुष्ट नहीं कर सका। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के किसी भी सदस्य देश ने संगत मानदंडों के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर चीन के उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया है।
 - (ii) जब तक चीन के प्रतिवादी निर्यातक नियमों के तहत विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करते निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करना चाहिए।
 - (iii) चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक/निर्यातक के बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच**चीन जन. गण. के उत्पादक का गैर-बाजार अर्थव्यवस्था दावा**

23. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विगत तीन वर्षों में भारत और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अन्य सदस्य देशों द्वारा पाटनरोधी जांच में एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है। चीन जन. गण. को नियमों के तहत निर्यातक देश अथवा व्यक्तिगत निर्यातकों द्वारा पूर्वानुमान का खंडन किए जाने के अध्यक्षीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है।
24. यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के तहत, यदि चीन जन. गण. से निर्यातक पैरा 8 में उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करें और इसे प्रतिकूल सिद्ध करे तो एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पूर्वानुमान को खंडित किया जा सकता है। चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं में सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्रावली के उत्तर में पैरा 8 के उप-पैरा (3) में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सके कि क्या:
- (i) कच्ची सामग्रियों, प्रौद्योगिकी की लागत और श्रम सहित कीमतों और इनपुट, आउटपुट, बिक्री तथा निवेश के संबंध में चीन जन. गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय आपूर्ति और मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतकों के प्रत्युत्तर में और इस संबंध में महत्वपूर्ण इनपुट की लागतें पर्याप्त रूप से बाजार के मूल्यों को दर्शाती हैं।
 - (ii) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतें और वित्तीय स्थिति पूर्व गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली, विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खाते, वस्तु विनिमय बाजार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के द्वारा भुगतान के संबंध में हुए महत्वपूर्ण बदलावों के अध्यक्षीन हैं।
 - (iii) ऐसी फर्मों दिवालिएपन और संपत्ति कानूनों के अध्यक्षीन हैं, जो कि फर्मों के प्रचालन के लिए कानूनी निश्चितता और स्थायित्व की गारंटी देते हैं।
 - (iv) विनिमय दर परिवर्तन बाजार की दर पर किए गए हैं।

25. यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी को उपरोक्त किसी भी मानदंड की जांच करने की आवश्यकता नहीं है और यह पाया है कि चीन जन. गण. से उत्पादक/निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत संचालित नहीं हो रहे हैं।

च. न जन. गण. में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

26. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से सूचना प्रदान करने के लिए उन्हें परामर्श देते हुए प्रश्नावली भेजी। निम्नलिखित पक्षकारों ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं:

चीन जन. गण.

- (i) शांगफोन हवाफोन स्टील कंपनी लि. (उत्पादक)
 - (ii) जियांगशू शागांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लि. (निर्यातक)
 - (iii) झांगजियांग शाजिंग हैवी प्लेट कंपनी लि. (उत्पादक)
 - (iv) शागांग इंटरनेशनल सिंगापुर प्रा. लि. (निर्यातक)
 - (v) किंगदाओ आरएचटी स्टील कं. लि. (निर्यातक)
 - (vi) मैसर्स जियांगिन जिंगचेंग स्पेशल स्टील वर्क्स कंपनी लि. (उत्पादक/ निर्यातक)
27. यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। अतः अनंतिम जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा रिकार्ड में रखे गए तथ्यों को देखते हुए, प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए निर्मित सामान्य मूल्य को अपनाया है।

चीन जन. गण. में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली

28. उपरोक्त को देखते हुए चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाना है। अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार, चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य का निर्धारण एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में घरेलू विक्री की कीमतों अथवा एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य अथवा ऐसे एक तीसरे देश से किसी अन्य देश को निर्यात कीमत, जिसमें भारत शामिल है, के आधार पर किया जाना है। तथापि, यदि सामान्य मूल्य का निर्धारण उपरोक्त विकल्पों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता तो निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं, जिसमें तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजन करते हुए समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जांच की जाने वाली कीमत शामिल है।
29. किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध वस्तुओं के लिए किसी भी विश्वसनीय कीमत और लागत संबंधी ब्यौरे उपलब्ध न होने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एक तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजन करते हुए समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। तदनुसार, चीन जन. गण. से सभी निर्यातकों के लिएके लिए सामान्य मूल्य का अनंतिम निर्धारण किया गया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन सारणी में दर्शाया गया है।

यूरोपीय संघ, उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ के किसी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जाँच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है और सहयोग नहीं किया है। यूरोपीय संघ में सभी गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने बेहतर उपलब्ध सूचना के आधार पर के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर अनंतिम भारित औसत सामान्य मूल्य निर्धारित किया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत

मैसर्स झांगजियांग शाजिंग हैवी प्लेट कंपनी लिमिटेड चीन जन. गण. (उत्पादक) द्वारा संबद्ध व्यापारियों मैसर्स जियांगशू शागांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लि चीन जन. गण. और मैसर्स शागांग इंटरनेशनल सिंगापुर प्रा. लि. सिंगापुर के माध्यम से निर्यात

31. मैसर्स झांगजियांग शाजिंग ह्यूवी प्लेट कंपनी लिमिटेड चीन जन. गण. ("शाजिंग") द्वारा दाखिल किए गए उत्तर से, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शाजिंग संबद्ध वस्तु का उत्पादक है। इसकी संबद्ध कंपनी, मैसर्स जियांगसू शागांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लि चीन जन. गण. ("शागांग इंटरनेशनल") ने एक अन्य संबद्ध कंपनी मैसर्स शागांग इंटरनेशनल सिंगापुर प्रा. लि. सिंगापुर ("शागांग एस जी") के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।
32. शागांग एसजी द्वारा प्रस्तुत सूचना से, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शागांग एसजी ने संबद्ध वस्तु की आगे सेगसंग सी और टी कारपोरेशन कोरिया ("सेगसंग") को पुनः बिक्री की है। सेमसंग ने कोई प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है। इसके अलावा, शाजिंग ने परिशिष्ट-2 में भारत को किसी निर्यात की सूचना नहीं दी है। उत्पादक से परिशिष्ट-2 सूचना के अभाव में यह संभव नहीं है कि भारत को कारखाना बाह्य निर्यात का पता लगाया जा सके।
33. अतः, सेगसंग द्वारा असहयोग किए जाने सहित शाजिंग से पूरी सूचना उपलब्ध न होने के कारण प्राधिकारी अनंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए शाजिंग द्वारा दाखिल उत्तर को स्वीकार नहीं करते। तदनुसार, शाजिंग के लिए निर्यात डाटा प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है।

शानडोंग ह्वाफोन स्टील शीट कंपनी लि. (उत्पादक) द्वारा असंबद्ध व्यापारी मैसर्स किंगदाओ आरएचटी स्टील कंपनी लिमिटेड के माध्यम से निर्यात

34. शानडोंग ह्वाफोन स्टील शीट कंपनी लि., चीन जन. गण. ("ह्वाफोन") द्वारा दाखिल उत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ह्वाफोन संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है और उसने असंबद्ध व्यापारी मैसर्स किंगदाओ आरएचटी स्टील कंपनी लिमिटेड ("आरएचटी") के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ह्वाफोन ने परिशिष्ट-2 में भारत को किसी निर्यात की सूचना नहीं दी है। उत्पादक से परिशिष्ट-2 सूचना के अभाव में यह संभव नहीं है कि भारत को कारखाना बाह्य निर्यात का पता लगाया जा सके।
35. अतः, ह्वाफोन द्वारा पूरी सूचना न देने के कारण प्राधिकारी अनंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए ह्वाफोन द्वारा दाखिल उत्तर को स्वीकार नहीं करते। तदनुसार, ह्वाफोन के लिए निर्यात डाटा प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है।

मैसर्स जियांगिन जिगचेंग स्पेशल स्टील वर्क्स कंपनी लि. (उत्पादक/ निर्यातक)

36. मैसर्स जियांगिन जिगचेंग स्पेशल स्टील वर्क्स कंपनी लि., चीन जन. गण. ("जेएक्सएसएस") द्वारा दाखिल की गई सूचना से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जेएक्सएसएस ने 6 एम एम से अधिक मोटाई वाली प्लेटों का निर्यात किया है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आती। अतः जेएक्सएसएस द्वारा प्रस्तुत सूचना की कोई जांच नहीं की गई।

चीन जन. गण. से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

37. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में चीन जन. गण. से किसी अन्य उत्पादक निर्यातक ने प्राधिकारी को कोई उत्तर नहीं दिया है। उपरोक्त उत्पादकों/ निर्यातकों, जिनका उत्तर प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, सहित चीन जन. गण. से सभी असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के लिए अनंतिम भारत औसत निर्यात कीमत का निर्धारण किया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

यूरोपीय संघ में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जाँच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिए हैं। यूरोपीय संघ में सभी गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी बेहतर उपलब्ध सूचना के आधार के लिए अनंतिम भारत औसत निर्यात कीमत निर्धारित की है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

पाटन मार्जिन

39. पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए सामान्य मूल्य के साथ भारत के लिए निर्यात कीमत (सभी निवल समायोजन) की तुलना की गई है। संबद्ध देशों से सभी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए जांच की अवधि के दौरान अनंतिम पाटन मार्जिन नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य (अम.डॉ./मी.ट.)	निबल निर्यात कीमत (अम.डॉ./मी.ट.)	पाटन मार्जिन (अम.डॉ./मी.ट.)	पाटन मार्जिन%	पाटन मार्जिन रेंज%
1	चीन जन. गण.	सभी	सभी	***	***	***	***	50-60
2	यूरोपीय संघ	सभी	सभी	***	***	***	***	70-80

40. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन काफी अधिक है और यह संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के सभी उत्पादकों-निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में नियमावली के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक है।

ख. क्षति**आयातकों, निर्यातकों, प्रयोक्ताओं और प्रयोक्ता एसोसिएशनों द्वारा किए गए निवेदन**

41. क्षति से संबंधित मुद्दों के बारे में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (i) याचिका में पाटन और क्षति का कोई पर्याप्त और पूर्ण प्रमाण निहित नहीं है।
- (ii) घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन स्थिर रहा है और उसमें सुधार हुआ है। पहुंच मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कीमत में कटौती हुई है, घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है।
- (iii) घरेलू उद्योग के प्रतिकूल निर्यात निष्पादन के कारण क्षति हुई है। चीन जनवादी गणराज्य से आयातों से भिन्न कारकों के कारण क्षति हुई है।
- (iv) प्रतिकारी उपायों की मांग अवांछनीय है।
- (v) क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त की गई कार्य प्रणाली में संशोधन करने की आवश्यकता है। डीजीएडी को नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ नहीं देना चाहिए। सेस्टेट द्वारा नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ देने का निर्णय अनुचित है। इसके अतिरिक्त किसी भी स्टील उत्पादक ने कभी भी नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ प्राप्त नहीं किया है।
- (vi) संचयन प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में संचयन उपयुक्त नहीं है क्योंकि चीन के आयात कुल आयातों का 84% भाग बनते हैं।
- (vii) घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि अधिकतर आर्थिक प्राचल सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाते हैं अथवा वे अधिकतर स्थिर हैं। उत्पादन, मांग, बिक्रियों, क्षमता और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है।
- (viii) घरेलू उद्योग को घाटा हो रहा है लेकिन वह क्षति निर्धारण के लिए विचारित अवधि के प्रारंभ में अर्थात् 2012-13 में पहले से ही घाटा उठा रहा था।
- (ix) अन्य कारकों के कारण क्षति हुई है जिसकी प्राधिकारी को जांच करने की आवश्यकता है।
- (x) क्षति निर्धारण के लिए विचारित अवधि से पहले से ही घरेलू उद्योग लाभ कमा रहा है। याचिकादाताओं ने वर्ष 2012-13 में पहले से ही घाटे उठाए थे।

- (xi) घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन कार्यकुशलता की समस्या के कारण उसके क्षमता उपयोग की दर लगभग 50 प्रतिशत के आस-पास घट-बढ़ रही है। निवेश के निर्णय और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने के कारण क्षति हुई है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

42. क्षति से संबंधित मुद्दों के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (i) समग्र जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पूर्णरूपेण वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में पूर्णरूपेण वृद्धि हुई है।
- (ii) उत्पादन के संबंध में तथा भारत में खपत के संबंध में संबद्ध वस्तुओं के आयात में पूर्णरूपेण वृद्धि हुई है।
- (iii) घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है, हालांकि भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो रही है। इसका यह कारण है कि आयातों ने मांग में होने वाली वृद्धि की तीव्रता से हथिया लिया है, जब कि संबद्ध देशों से आयातों के बाजार के हिस्से में वर्ष 2012-13 से ले कर जांच अवधि (वार्षिकीकृत) में तेजी से वृद्धि हुई है।
- (iv) घरेलू उद्योग, मांग में ऐसी वृद्धि के समनुरूप अपने उत्पादन और बिक्रियों को बढ़ाने में सक्षम नहीं हुआ है।
- (v) घरेलू उद्योग की मालसूचियों में भी वृद्धि हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग, मांग में वृद्धि होने के बावजूद भी अपनी बिक्रियां बढ़ाने में सक्षम नहीं हो सका है। आयात भारत में मांग को तेजी से अधिग्रहीत कर रहे हैं।
- (vi) भारत में होने वाले कम कीमत पर पाटित आयातों के कारण अत्यधिक कीमतह्रास और न्यूनीकरण हो रहा है।
- (vii) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता विकट रूप से प्रभावित हुई है। समस्त क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता में नकारात्मक प्रवृत्ति रही है और जांच अवधि के दौरान घाटे और भी बदतर हो गए हैं।
- (viii) घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन ने किसी भी तरीके से उसकी वित्तीय और आर्थिक स्थिति को प्रभावित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त याचिकादाताओं ने क्षति के प्राचलों की जांच करते समय निर्यातों से संबंधित सूचना की भी अनदेखी की है तथा समग्र क्षति विश्लेषण, केवल याचिकादाताओं के घरेलू कार्य-निष्पादन पर आधारित है।
- (ix) ऐसे विश्लेषण से अत्यधिक ऐसा पता चलता है कि घरेलू उद्योग को भारत में विचाराधीन उत्पादों के बढ़ रहे पाटित आयातों के कारण आर्थिक क्षति हो रही है। संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में वृद्धि होने तथा घरेलू उद्योग को हो रही आर्थिक क्षति के बीच सुदृढ़ संबंध विद्यमान होने का पता चलता है।
- (x) हितबद्ध पक्षकारों ने यह निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति अन्य कारक और अत्यधिक क्षमताओं के कारण हुई है। ये दावे बहुत सामान्य हैं और बिना किसी तथ्यों के हैं तथा उनके समर्थन में कोई आंकड़े नहीं हैं। यह तथ्य कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है, पहले ही प्रमाणित हो चुका है। घरेलू उद्योग अनेक वर्षों से विद्यमान है और उसने विगत में अच्छा कार्य किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

43. क्षति और कारणात्मक संबंधों के बारे में जांच की कार्यवाही के दौरान घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदनों की जांच की गई है और उनका निदान निम्नानुसार किया गया है:-

- (i) प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के पहुंच मूल्य में गिरावट आई है तथा घरेलू उद्योग ऐसी कम कीमतों के अनुरूप अपनी कीमतों को बनाए रखने के लिए बाध्य हुए हैं जिसके कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हो रही है।
- (ii) घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि समग्र क्षति विश्लेषण केवल याचिकादाताओं के घरेलू कार्य-निष्पादन पर आधारित है।
- (iii) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों ने इस तर्क का और विश्लेषण किया है कि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण क्षति हो रही है। ये दावे बहुत सामान्य हैं और बिना किसी तथ्यों के हैं तथा उनके समर्थन में कोई आंकड़े नहीं हैं। यह तथ्य कि भारत में संबद्ध

वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है, जिसे परवर्ती पैराओं में प्रमाणित किया गया है। संबद्ध वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग के पास इन्फ्रास्ट्रक्चर और क्षमताएं विद्यमान हैं।

- (iv) नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ स्वीकृत करने के मुद्दे पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियोजित पूंजी पर 22% लाभ देना प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा है।

संचयी मूल्यांकन

44. विश्व व्यापार संगठन करार के अनुच्छेद 3.3 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (iii) में यह उपबंध है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि:-

- (i) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत से कम है (अथवा अधिक है) वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयात के साथ सबसे अधिक बनता है; तथा
- (ii) आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि

- (i) संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। ऐसे प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन, नियमावली में निर्धारित न्यूनतम सीमा से बहुत अधिक है।
- (ii) ऐसे प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा आयातों की कुल मात्रा से 3% से भी अधिक है।
- (iii) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल उनके द्वारा पेश की जा रही समान वस्तुओं से सीधे प्रतिस्पर्द्धा करते हैं, बल्कि वे भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की जा रही समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।

46. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों से संचयी रूप से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मूल्यांकन करना उपयुक्त होगा।

47. पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 के साथ पठित उसके अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि क्षति का निर्धारण करने की जांच में "..... सभी संबद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में उनकी कीमतों पर प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव शामिल हैं....." ऐसे कारकों की जांच करना शामिल है, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति होने का पता चलता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक समझा गया है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली इस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकों जैसे कि उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार किया गया है।

पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

मांग का मूल्यांकन

48. संबद्ध वस्तुओं की मांग का निर्धारण, सभी देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के साथ समान उत्पाद के भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों को जोड़ कर किया गया है। वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने सीबीईसी से प्राप्त किए गए आयात के आंकड़ों पर विश्वास किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे तालिका में देखा जा सकता है :-

विवरण (मी.ट.)	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 2015- दिसंबर 2015 (ए)	जांच अवधि (जुलाई 2015- दिसंबर 15)	जांच अवधि (ए)
संबद्ध देशों से कुल पाटित आयात	60,771	73,854	209,895	412,322	213,311	426,622
अन्य देशों से आयात	41	304	0	192	0	0
कुल आयात	60,812	74,159	209,895	412,513	213,311	426,622
याचिकादाताओं की घरेलू बिक्रियां	230,213	327,096	308,076	415,032	190,574	381,148
अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्रियां	226,878	173,687	193,691	225,007	111,402	222,803
कुल मांग/प्रत्यक्ष खपत	517,903	574,942	711,662	1,052,552	515,287	1,030,573

आयात की मात्रा और संबद्ध देशों का हिस्सा

49. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या पाटित आयातों में पूर्णरूपेण अथवा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में अत्यधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा का विश्लेषण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

विवरण (मी.ट. में)	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 2015- दिसंबर 2015 (ए)	जांच अवधि (जुलाई 2015- दिसंबर 15)	जांच अवधि (ए)
संबद्ध देशों से पाटित आयात	60,771	73,854	209,895	412,322	213,311	426,622
प्रवृत्ति	100	122	345	678	351	702
अन्य देशों से आयात	41	304	0	192	0	0
प्रवृत्ति	100	748	-	471	-	-
कुल आयात	60,812	74,159	209,895	412,513	213,311	426,622
प्रवृत्ति	100	122	345	678	351	702
कुल मांग/प्रत्यक्ष खपत	517,903	574,942	711,662	1,052,552	515,287	1,030,573
प्रवृत्ति	100	111	137	203	99	199
खपत के प्रसंग में संबद्ध देशों से पाटित आयात	11.73%	12.85%	29.49%	39.17%	41.40%	41.40%
याचिकादाताओं का उत्पादन	413,999	574,789	557,496	591,385	276,418	552,835

विवरण (मी.ट. में)	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 2015- दिसंबर 2015 (ए)	जांच अवधि (जुलाई 2015- दिसंबर 15)	जांच अवधि (ए)
याचिकादाताओं के कुल उत्पादन के प्रसंग में संबद्ध देशों से पाटित आयात	14.68%	12.85%	37.65%	69.72%	77.17%	77.17%

50. प्राधिकारी उपरोक्त तालिका से निम्नानुसार नोट करते हैं:

- (i) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पूर्णतया वृद्धि हुई है जोकि वर्ष 2012-13 में 71,342 मी.ट. से बढ़कर जांच अवधि में 422,816 मी.ट. (ए) हो गए हैं।
- (ii) याचिकादाताओं के उत्पादन के प्रसंग में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पूर्णतया वृद्धि हुई है जोकि वर्ष 2012-13 में 17.2 % से बढ़कर जांच अवधि में 76.5 % (ए) हो गए हैं।
- (iii) भारत में खपत के प्रसंग में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पूर्णतया वृद्धि हुई है जोकि वर्ष 2012-13 में 11.8 % से बढ़कर जांच अवधि में 39.5 % (ए) हो गए हैं।

51. इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पूर्णरूपेण और भारत में उत्पादन और खपत दोनों के संबंध में संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई है।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के कीमत प्रभाव

52. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध-11 (ii) में निम्नानुसार निर्धारित है :

“जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।”

53. इसकी जांच की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत के पाटित आयातों द्वारा कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव अन्यथा कीमतों को ह्रास करने पर पड़ते अथवा कीमत में होने वाली वृद्धि को रोकते जो कि अन्यथा अत्यधिक स्तर तक होती। कीमत में कटौती होने, कम कीमत पर बिक्री होने, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण यदि कोई हुआ है, के संदर्भ में घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की गई।

कीमत में कटौती

54. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली के साथ की है। इस संबंध में घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत की तुलना निर्यातित उत्पाद के पहुंच मूल्य और व्यापार के समान स्तर पर सभी रिबेटों और करों को छोड़कर घरेलू बाजार के लिए घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के साथ की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण कारखानागत स्तर पर किया गया था। घरेलू कीमतों और कीमत में कटौती के मार्जिन को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

कीमत कटौती	जुलाई 15 से दिसंबर 15	चीन जनवादी गणराज्य	यूरोपीय यूनियन
पहुंच मूल्य	रूपए /मी.टन	***	***
घरेलू बिक्री कीमत	रूपए /मी.टन	***	***

कीमत कटौती	रूपए /मी.टन	***	***
कीमत कटौती	एल वी का %	***	***
कीमत कटौती की सीमा		20-30%	35-45%

55. प्राधिकारी उपरोक्त तालिका से यह नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य के साथ-साथ यूरोपीय यूनियन के लिए अत्यधिक कीमत कटौती विद्यमान है। इतनी अधिक कीमत कटौती होने के कारण घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमतों को बढ़ाने में असमर्थ है जिससे कि वह अपनी लागत को वसूल कर सके तथा प्रतिलाभ की उचित दर अर्जित कर सके। यदि घरेलू उद्योग आयातों के प्रत्युत्तर में अपनी कीमतों को कम नहीं करता है, तो वह और अधिक ग्राहकों को गंवा देगा तथा उसकी क्षति और अधिक विकट हो जाएगी।

कम कीमत पर बिक्री

56. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा कम कीमत पर बिक्री किए जाने की स्थिति की भी जांच की है। इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत की तुलना आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है। घरेलू उद्योग की भारित औसत क्षति रहित कीमत की आयातों की औसत पहुंच कीमत के साथ की गई तुलना को निम्नानुसार दर्शाया जाता है:-

कम कीमत पर बिक्री	जुलाई 15 से दिसंबर 15	चीन जनवादी गणराज्य	यूरोपीय यूनियन
पहुंच मूल्य	रूपए /मी.टन	***	***
क्षतिरहित कीमत	रूपए /मी.टन	***	***
क्षति मार्जिन	रूपए /मी.टन	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***
क्षति मार्जिन की सीमा	%	30-40%	50-60%

57. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत से अत्यधिक कम थी।

कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

58. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से काफी हद तक कीमतों में ह्रास हुआ है अथवा कीमतों में वृद्धि होना रुका है, जो कि अन्यथा काफी हद तक हो सकती थी, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में परिवर्तन होने पर विचार किया है। इसकी स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है:-

विवरण (रू. प्रति मी.ट.)	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 2015- दिसंबर 2015	जांच अवधि (जुलाई 2015- दिसं 15)
निर्माण व बिक्री लागत	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	104	106	95	94
घरेलू बिक्री कीमत	***	***	***	***	***

प्रवृत्ति	100	104	105	93	91
पहूँच मूल्य	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	111	109	101	98

59. यह नोट किया जाता है कि घरेलू बिक्री कीमत में गिरावट बिक्रियों की लागत में गिरावट से अधिक है। समस्त जांच अवधि के दौरान आयात की कीमतें, घरेलू बिक्री कीमतों के साथ-साथ घरेलू उद्योग के लिए निर्माण और बिक्री की लागत से अत्यधिक कम बनी रही हैं। कम कीमत के पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को ऐसी बिक्री कीमत प्राप्त करने की भी स्वीकृति नहीं दी है जिससे कि वह अपनी लागत को भी वसूल कर सके। इस प्रकार, आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास कर रहे हैं।

घरेलू उद्योग के आर्थिक प्राचल

60. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में क्षति का निर्धारण करने के लिए समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों की परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त नियमों में ऐसा भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संबद्ध आर्थिक कारकों और सूचकों का सार्थक और निष्पक्ष मूल्यांकन करना निहित है, जिनमें बिक्रियों, लाभ, आउटपुट, बाजार का हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह, माल सूचियों, रोजगार, वेतन, संवृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच करने से ऐसा पता चला है कि घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग की क्षति से संबंधित विभिन्न प्राचलों का उल्लेख नीचे किया गया है।

उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

61. उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार था:-

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 2015- दिसंबर 2015 (ए)	जांच अवधि (जुलाई 2015- दिसंबर 15)	जांच अवधि (ए)
स्थापित क्षमता (मी.ट.)	868,000	1,093,000	1,093,000	1,093,000	546,500	1,093,000
कुल उत्पादन (मी.ट.)	413,999	574,789	557,496	591,385	276,418	552,835
क्षमता उपयोग	47.70%	52.59%	51.01%	54.11%	50.58%	50.58%
घरेलू बिक्रियां	230,213	327,096	308,076	415,032	190,574	381,148

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन पाटित आयातों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग क्षति की जांच अवधि के दौरान अनुकूलतम क्षमता उपयोग नहीं कर पाया है।

लाभप्रदता

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 2015- दिसंबर 2015 (ए)	जांच अवधि (जुलाई 2015- दिसंबर 15)	जांच अवधि (ए)
लाभ (करोड़ रु० में)	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	(100)	(150)	(166)	(253)	(127)	(254)
लाभ (रू./मी.ट.)	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	(100)	(106)	(124)	(140)	(153)	(153)
नकद लाभ (करोड़ रु० में)	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	(100)	(133)	(174)	(282)	(144)	(287)
नकद लाभ (रू./मी.ट.)	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	(100)	(94)	(130)	(156)	(174)	(174)

63. प्राधिकारी उपरोक्त तालिका से निम्नोक्त नोट करते हैं :

- (i) संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा बड़े हुए पाटन के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हुए घाटों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- (ii) जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से घोर पाटन होने के कारण घरेलू उद्योग उचित लाभ कमाना तो दूर बल्कि बिक्रियों की अपनी लागत को वसूल करने में भी समर्थ नहीं हुआ है।
- (iii) इसलिए यह निष्कर्ष है कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता को विकट रूप से प्रभावित किया है।

बाजार का हिस्सा

64. घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की गई है, जो कि निम्नानुसार है:

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015- Dec 2015 (A)	POI (Jul 2015- Dec 15)	POI (A)
मांग (मी.ट.)	517,903	574,942	711,662	1,052,552	515,287	1,030,573
सूचीबद्ध	100	111	137	203	99	199
बाजार हिस्सा						
याचिकादाताओं का हिस्सा	44.45%	56.89%	43.29%	39.43%	36.98%	36.98%
अन्य उत्पादकों का हिस्सा	43.81%	30.21%	27.22%	21.38%	21.62%	21.62%
संबद्ध देशों का हिस्सा	11.73%	12.85%	29.49%	39.17%	41.40%	41.40%

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015- Dec 2015 (A)	POI (Jul 2015- Dec 15)	POI (A)
अन्य देशों का हिस्सा	0.01%	0.05%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%

65. उपर्युक्त तालिका से प्राधिकारी ने यह देखा है कि हालांकि भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो रही है, फिर भी घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है। इसका कारण यह है कि आयातों ने मांग में हुई वृद्धि को तीव्रता से अधिग्रहीत कर लिया है।
66. याचिकादाता संबद्ध देशों से होने वाले पाटित आयातों की अत्यधिक मात्रा के कारण मांग में वृद्धि होने के समनुरूप विचाराधीन उत्पाद की बिक्रियां बढ़ाने में सक्षम नहीं हो सके हैं।

माल सूचियां

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि (जुलाई 2015- दिसंबर, 15)
औसत मालसूची (मी.ट.)	***	***	***	***
प्रवृत्ति (सूचीबद्ध)	100	136	141	229

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अत्यधिक जमा हुई मालसूचियों का सामना कर रहा है। आधार वर्ष की तुलना में मालसूचियों के स्तर में वृद्धि हो रही है। आयातों के बढ़ने के कारण घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्सा घट गया है और आयातों ने बड़ी हुई मांग को हथिया लिया है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अपने उत्पादन और बिक्रियों को बढ़ाने में असमर्थ है जिसके फलस्वरूप क्षति अवधि के दौरान मालसूचियों के इकट्ठे जमा होने की स्थिति हो गई है।

संवृद्धि

विवरण	Unit	2013-14	2014-15	जांच अवधि (ए)
उत्पादन की लागत	%	4%	2%	-11%
बिक्री कीमत	%	4%	1%	-13%
हानि	%	50%	11%	53%
नकद हानि	%	33%	31%	65%
बाजार का हिस्सा	%	12%	-24%	-16%

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता उपयोग, लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, नकदी लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग की संवृद्धि नकारात्मक रही है।

पूँजीगत निवेश जुटाने की क्षमता

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने देश में उत्पाद की मांग बढ़ने की स्थिति को ध्यान में रख कर संयंत्र और मशीनरी में निवेश किया है। तथापि, इन निवेश के बावजूद घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में अत्यधिक गिरावट आई है और इससे और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

पाटन का स्तर और पाटन मार्जिन

70. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं और पाटन का मार्जिन अत्यधिक है।

घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

71. संबद्ध देशों से आयात कीमतों की जांच करने, लागत के ढांचे में परिवर्तन होने, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धा होने, पाटित आयातों से भिन्न कारकों से जो कि घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करते हैं, आदि से ऐसा पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से काफी कम है, जिसके कारण भारतीय बाजार में अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री हो रही है। इस प्रकार घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य है।

क्षति पर निष्कर्ष

72. इस प्रकार यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से पूर्णरूपेण पाटितआयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारत में उत्पाद की खपत और उत्पादन के संबंध में आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार भारत में उत्पाद की खपत और उत्पादन दोनों के संबंध में आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पाटित आयातों का कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के रूप में कीमत पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पाटित आयातों के प्रभाव के फलस्वरूप संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतें कम हुई हैं। कम कीमत के पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को बाजार कीमत प्राप्त करने के लिए विवश कर दिया है जो कि उसकी लागत को भी वसूल नहीं कर सकी है। घरेलू उद्योग को अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री करने पर क्षति हो रही है। भारत में कम कीमत पर पाटित आयातों के प्रवेश करने से अत्यधिक कीमत ह्रास और न्यूनीकरण की स्थिति विद्यमान है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन बहुत अधिक है। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के बारे में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातने ने उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता उपयोग, माल सूचियों, बाजार के हिस्से, लाभ, नकदी लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। घरेलू उद्योग की मालसूचियों में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता विकट रूप से प्रभावित हुआ है। तथ्य से यह प्रमाणित होता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को अत्यधिक घाटे हुए हैं। इस प्रकार प्राधिकारी का अनन्तिम रूप से यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।

कारणात्मक संबंध

73. प्राधिकारी ने इसकी जांच की है कि क्या पाटन-रोधी नियमावली में सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। पाटन और घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति होने के बीच कारणात्मक संबंधों की जांच की गई है, जो कि निम्नानुसार है।

तृतीय देशों से आयात

74. संबद्ध देशों से भिन्न अन्य देशों से आयात मात्रा की दृष्टि से अधिक नहीं हैं जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने का खतरा हो। इसके अतिरिक्त जिन कीमतों पर अन्य देशों से वस्तुएं आ रही हैं, वे संबद्ध देशों से आने वाली वस्तुओं की कीमतों से बहुत अधिक हैं।

मांग में संकुचन

75. संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है। इसलिए मांग में कमी होना, घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं हो सकता है। वास्तव में घरेलू उद्योग मांग में हुई वृद्धि के समनुरूप अपनी बिक्रियों और बाजार के हिस्से को बढ़ाने में सक्षम नहीं हुआ है।

विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापारिक प्रतिबंधित प्रवृत्तियां और उनके बीच प्रतिस्पर्द्धा

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धति नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

प्रोद्योगिकी में विकास

77. संबद्ध उत्पाद के उत्पादन की प्रोद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रोद्योगिकी में विकास को घरेलू उद्योग की क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

खपत के पैटर्न में परिवर्तन

78. घरेलू उद्योग ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, जिनका भारत में आयात किया गया है। खपत के पैटर्न में संभावित परिवर्तन घरेलू उद्योग की क्षति का कारक नहीं हो सकता है।

निर्यात निष्पादन

79. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति के लिए घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित अधिक गिरावट आने का कारण नहीं माना जा सकता है। वास्तव में भौतिक दृष्टि से घरेलू उद्योग के निर्यात में कोई गिरावट नहीं आई है। फिर भी घरेलू उद्योग के घरेलू कार्य-निष्पादन पर विचार किया गया है।

अन्य देशों के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन ने घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन के प्राधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन को प्रभावित नहीं किया है। प्राधिकारी द्वारा केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना पर विचार किया गया है।

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को उत्पादकता में गिरावट आने के कारण क्षति नहीं हुई है।

कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक

82. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन के विश्लेषण से ऐसा पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में भौतिक दृष्टि से गिरावट आई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध होने की संपुष्टि निम्नोक्त आधार पर हुई है:-

- समग्र जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पूर्णरूपेण वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में पूर्णरूपेण वृद्धि हुई है।
- भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि हुई है।
- हालांकि भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है, फिर भी घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है। इसका यह कारण है कि आयातों ने मांग में हुई वृद्धि को तेजी से हथिया लिया है।
- घरेलू उद्योग मांग में हुई वृद्धि के समतुल्य अपने उत्पादन और बिक्रियों को बढ़ाने में समर्थ नहीं हुआ है।
- भारत में प्रवेश करने वाले कम कीमत के पाटित आयातों के कारण कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास हो रहा है।
- घरेलू उद्योग की लाभप्रदता विकट रूप से प्रभावित हुई है। तथ्य से यह प्रमाणित होता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को अत्यधिक घाटे हुए हैं।

83. उपरोक्त विश्लेषण से ऐसा पता चलता है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के बढ़ते पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हो रही है। इस प्रकार संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में वृद्धि होने और घरेलू उद्योग को हो रही आर्थिक क्षति के बीच सुदृढ़ संबंध विद्यमान है।

क्षति और कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

84. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में उपरोक्त जांच से प्राधिकारी का अनन्तिम रूप से यह निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है। समस्त क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में पूर्णरूपेण वृद्धि हुई है। पाटित आयातों ने बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव डाला है। संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और इसे अत्यधिक माना गया है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने उत्पादन, विक्रियों और क्षमता उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में अत्यधिक गिरावट आई है जबकि संबद्ध आयातों के बाजार के हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के कार्य-निपादन में लाभ, नकदी लाभ के संबंध में अत्यधिक गिरावट आई है। उसकी मांग सूचियों में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी का अनन्तिम रूप से यह निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।
85. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है और उसकी तुलना प्रतिवादी निर्यातकों के संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्यों के साथ की है ताकि क्षति मार्जिन का निर्धारण किया जा सके। अनन्तिम रूप से निर्धारित किया गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:-

क्षति मार्जिन

क्रमांक	देश	उत्पादक	निर्यातक	क्षति रहित कीमत (अम.डॉ./मी.ट.)	पहुंच मूल्य (अम.डॉ./मी.ट.)	क्षति मार्जिन (अम.डॉ./मी.ट.)	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन की सीमा %
1.	चीन जन.गण	सभी	सभी	***	***	***	***	30-40
2.	ईयू	सभी	सभी	***	***	***	***	50-60

86. यथा निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन अत्यधिक पाया गया है।

झ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में समान अवसरों वाली स्थिति सृजित करके खुली और उचित प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटन-रोधी उपाय लागू करना संबद्ध देश से आयातों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करेगा और इसलिए उपभोक्ता को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं करेंगे।

88. यह माना जाता है कि पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं को इस्तेमाल करके विनिर्मित किए उत्पाद के कीमत के स्तर को प्रभावित हो सकते हैं और उसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की सापेक्ष प्रतिस्पर्द्धात्मकता कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है। घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि प्रस्तावित शुल्क लगाए जाने से उपभोक्ताओं के लिए लागत संबंधी नगण्य प्रभाव पड़ेंगे। इसलिए पाटन-रोधी उपाय लागू किए जाने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा कम नहीं होगी, विशेषकर यदि पाटन-रोधी शुल्क ऐसी राशि तक सीमित रहते हैं, जो कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत पाटन-रोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन की पद्धतियों द्वारा प्राप्त किए गए अनुचित लाभ समाप्त होंगे और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट की रोकथाम होगी तथा ये उपभोक्ताओं को उनकी व्यापक रुचि की संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता को बनाए रखने में सहायक होंगे।

ब. सिफारिशें

89. किए गए निवेदनों और उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी अनन्तिम रूप से यह निष्कर्ष देते हैं कि-

- (क) भारत में संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के निर्यात, सामान्य मूल्य से कम पर किए गए हैं।
- (ख) संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।
- (ग) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसके बारे में अधिसूचित किया गया था। निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सार्थक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त समय दिया गया था। पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू किए जाने और उसका संचालन करने तथा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में निश्चयात्मक पाटन मार्जिन के साथ-साथ ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई आर्थिक क्षति और खतरा होने की पुष्टि हो जाने पर, प्राधिकारी का यह विचार है कि मौजूदा मामले में पाटन और "क्षति" को दूर करने के लिए निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है।

91. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम और क्षति मार्जिन से कम मार्जिन के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी द्वारा तदनुसार केन्द्रीय सरकार से संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य और नीचे तालिका के कॉलम 8 में निर्दिष्ट राशि के बीच के अंतर के बराबर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके, बशर्ते कि पहुंच मूल्य, कॉलम 8 में निर्दिष्ट मूल्य से कम हो। इस प्रयोजनार्थ का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) द्वारा यथा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3 क, 8 ख, 9 और 9 क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर, सभी शुल्क शामिल होंगे।

शुल्क तालिका

क्रमांक	शीर्ष/उप-शीर्ष	वस्तुओं का विवरण**	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	7210, 7212, 7225 तथा 7226	क्वायलों में अथवा क्वायलों के बिना चाहे मेटेलिक कोटेड हैं अथवा नहीं, जिंक, के मेटेलिक कोटेड एल्यूमिनियम जिंक अथवा कोई अन्य सबटेक्ट कोटिंग के प्री-पेंटेड, पेंटेड, रंगीन कोटेड अथवा आर्गेनिक कोटेड फ्लैट स्टील के उत्पाद	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	कोई भी	कोई भी	849	मी.ट.	अम. डॉ.

2.	- वही -	- वही -	चीन जन. गण.	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश	कोई भी	कोई भी	849	मी.ट.	अम. डॉ.
3.	- वही -	- वही -	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश	चीन जन. गण.	कोई भी	कोई भी	849	मी.ट.	अम. डॉ.
4.	- वही -	- वही -	यूरोपीय यूनियन	यूरोपीय यूनियन	कोई भी	कोई भी	849	मी.ट.	अम. डॉ.
5.	- वही -	- वही -	यूरोपीय यूनियन	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश	कोई भी	कोई भी	849	मी.ट.	अम. डॉ.
6.	- वही -	- वही -	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश	यूरोपीय यूनियन	कोई भी	कोई भी	849	मी.ट.	अम. डॉ.

ट. आगे की प्रक्रिया

92. प्रारंभिक जांच परिणाम को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:-

- (i) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन अनन्तिम जांच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करेंगे और प्राधिकारी द्वारा उनको प्रासंगिक पाए जाने पर उन पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा।
- (ii) प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों, आयातकों, आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों की चिंताओं का पृथक् रूप से निदान किया जाएगा, जो कि इन प्रारंभिक जांच परिणामों की अधिसूचना की तारीख से चालीस दिनों के भीतर उन्हें अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इन परिणामों के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर उन्हें अपने विचारों से अवगत करा सकता है।
- (iii) प्राधिकारी जितना आवश्यक समझा जाएगा, उतनी आगे और जांच करेंगे।
- (iv) प्राधिकारी अंतिम परिणाम घोषित करने से पहले पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार अत्यावश्यक तथ्यों को प्रकट करेंगे।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2016

Preliminary Findings

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Colour coated / pre-painted flat products of alloy or non-alloy steel” originating in or exported from China PR and European Union-reg.

No.14/28/2016-DGAD: Having regard to Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules).

2. Whereas M/s. Essar Steel India Limited and M/s. JSW Steel Coated Products Limited (hereinafter referred to as the “applicants” or “domestic industry”) have jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and the AD Rules, for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of color coated/ pre-painted flat products of alloy or non-alloy steel (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “Product Under Consideration”), originating in or exported from China PR and European Union (hereinafter also referred to as the “subject countries”) alleging dumping and consequent injury and requested for levy of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries.
3. And whereas the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicants, issued a public notice vide Notification No.14/28/2016-DGAD dated 29.06.2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed:
 - (i) The Authority notified the Delegation of the European Union to India representing European Union (EU) and the Embassy of China PR in India about the receipt of application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the AD Rules.
 - (ii) The Authority sent a copy of initiation notification to the Delegation of the European Union to India and the Embassy of China PR in India, known producers/ exporters from the subject countries and known importers/ users/ associations of the subject goods as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.

- (iii) The Authority forwarded a copy of the non-confidential version of application to the Delegation of the European Union to India and the embassy of China PR in India, known producers/exporters from the subject countries and known importers of the subject goods, in accordance with the AD Rules. A copy of the application was also provided to other interested parties, wherever requested.
- (iv) The Delegation of the European Union to India and the embassy of China PR in India were also requested to advise the producers/exporters from their countries to file their responses within the prescribed time limits.
- (v) The Authority sent exporter's questionnaires to the following known exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules to elicit relevant information:

European Union (EU)

1. Steel Coat Europe Alleur (Arcelor Mittal)
2. ThyssenKrupp Steel Europe AG
3. Tata Corus
4. SSAB
5. Metal Trade Comax
6. Voestalpine AG

China PR

1. Shanghai Metal Corporation
2. Baosteel Group Corporation
3. Sino East Steel Enterprise Co. Ltd
4. Qingdao Sino Steel Co. Ltd
5. Shanghai Color Steel Co. Ltd

- (vi) In response to the initiation notification, the following exporters/producers from the subject countries and traders have filed exporter's questionnaire:

China PR

1. Shandong Hwafone Steel Co. Ltd. (Producer)
2. Jiangsu Shagang International Trade Co. Ltd. (Exporter)
3. Zhnagjiagang Shajing Heavy Plate Co. Ltd (Producer)
4. Shagang International Singapore Pte Ltd (Exporter)
5. Qingdao RHT Steel Co. Ltd. (Exporter)
6. M/s Jiangyin Xingcheng Special Steel Works, Co., Ltd (Producer/Exporter)

- (vii) None of the producers/exporters from China PR has claimed Market Economy Treatment (MET) rebutting the non-market economy presumption in the present investigation.
- (viii) Questionnaires were sent to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
1. Sungreen Ventilation Systems (P) Limited
 2. Shree Rama Steel Syndicate,
 3. Indian Pipes Pvt. Ltd.
 4. Metal Shine Roofing,
 5. Brijlal & Sons
 6. Kumar Corporation
 7. Oriental Metals India Pvt. Ltd.

8. M.K.K. Metal Sections Pvt Ltd
 9. Kusum Metals Pvt Ltd
 10. Steel Co,
 11. Shanker Mercantile Pvt Ltd
 12. G M Traders
 13. PB Traders Private Limited
 14. Whirlpool Of India Ltd.
 15. Samsung India Electronics Pvt.Ltd.
- (ix) None of the importers/users of the subject goods has responded in the form of questionnaire responses or provided comments to the initiation of the investigation except Whirlpool of India Ltd.
- (x) Further, the following parties have filed submissions/comments on the initiation notification.
1. Delegation of European Union to India
 2. Whirlpool of India Ltd
 3. M/s Jiangyin Xingcheng Special Steel Works, Co., Ltd, China PR
 4. China Chamber of International Commerce
- (xi) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all interested parties have been taken into account in the present finding.
- (xii) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- (xiii) Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary.
- (xiv) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- (xv) The Non-Injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- (xvi) Considering the fact that the subject goods are being imported in various grades/sizes/dimensions, the applicants have also proposed Product Control Numbers (PCNs) in order to make a PCN to PCN comparison for computing the dumping margin and injury margin. However, for the purpose of preliminary findings, the authority has not adopted PCN to PCN comparison.

- (xvii) Verification of the information provided by the applicant domestic industry was carried out by the Authority to the extent deemed necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present preliminary findings.
- (xviii) Investigation was carried out for the period starting from 1st July 2015 to 31st December 2015 (6 months) (hereinafter referred to as the 'period of investigation' or the 'POI'). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from 2012-13, 2013-14, 2014-15, April 2015 to December 2015 and the POI.
- (xix) The petitioners had submitted the petition alleging dumping of the subject goods from the subject countries relying upon transaction wise imports data sourced from IBIS. However, request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to provide the transaction wise details of the imports of the subject goods for the past three years, including the period of investigation. The Authority has relied upon the data provided by the Directorate of Data Management, CBEC, in the preliminary findings.
- (xx) Arguments raised and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in the preliminary findings.
- (xxi) Exchange rate for conversion of US\$ to INR is considered for the POI as INR 65.93 as per customs data.
- (xxii) In this notification *** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

5. The product under consideration (PUC) in the present investigation is pre-painted, painted, colour coated or organic coated flat steels in coils or not in coils whether or not with metallic coated substrate of zinc, aluminium-zinc or any other substrate coating. These steels are either of alloy or non-alloy steel whether or not of prime or non-prime quality, either in the form of coils or plain sheets or profiled sheets including but not limited to trapezoidal, sinusoidal, corrugated or any other type of profiles. These products are available in various paint qualities and a variety of paint colours whether or not pre-coated with primer or any other suitable material. These steels may either be painted on top surface of the steel sheet or on bottom surface or on both top and bottom surfaces. This product may be supplied with or without guard film / lamination.
6. PUC offers resistance to corrosion along with barrier protection. PUC is used in many applications and sectors including but not limited to construction, roofing, walling, panelling, cladding and decking, automotive, white goods & appliances and furniture etc.
7. The PUC is classified under tariff item 72107000, 72124000, 72259900 and 72269990 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the imports have also been observed in certain other ITC HS Codes viz. 72101110, 72101190, 72101210, 72101290, 72103010, 72103090, 72104100, 72104900, 72105000, 72106100, 72106900, 72109010, 72109090, 72121010, 72121090, 72122090, 72123090, 72125020, 72125090, 72126000, 72255030, 72259200 and 72261100. The Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Submissions made by Exporters, Importers, Users and Other Interested Parties

8. Submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to issues related to PUC and considered relevant by the Authority are as follows:

- (i) The dumping and injury calculations should take into account different types of products and qualities.
- (ii) One of the exporters has submitted that they export middle or heavy plate with a thickness of 6mm or more to India which is painted with one kind of shop primer. This product is not covered within the scope of the PUC but even then they have filed exporter questionnaire response as abundant caution. There is difference between the applications of the PUC and product exported by the exporter. In general, the thickness of the PUC is less than 6mm.

Submissions made by Domestic Industry

9. The submissions made by the domestic industry (DI) and considered relevant by the Authority are as follows:

- (i) Domestic Industry has submitted that PUC covers all coated products whether pre-painted, painted, colour coated or organic coated flat steels in coils whether or not with metallic coated substrate of zinc, aluminium-zinc or any other substrate coating. These steels are either of alloy or non-alloy steel whether or not of prime or non-prime quality, either in the form of coils or plain sheets or profiled sheets including but not limited to trapezoidal, sinusoidal, corrugated or any other type of profiles.
- (ii) With regard to the submission of the exporter that heavy plates with thickness of 6mm or more may be kept out of the PUC, the Domestic Industry submits that this contention may be accepted as these plates are already not covered within the scope of the PUC.

Examination by the Authority

10. The submissions made by the interested parties and the domestic industry with regard to the PUC related issues and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

- (i) Domestic industry has submitted that the PUC covers steels either of alloy or non-alloy steel whether or not of prime or non-prime quality, either in the form of coils or plain sheets or profiled sheets including but not limited to trapezoidal, sinusoidal, corrugated or any other type of profiles. Accordingly, the PUC does not cover plates of thickness 6mm or more. Since, this product is not covered within the scope of the PUC, there is no need to grant any specific exclusion to this product.
- (ii) With regard to like article, Rule 2(d) of the AD Rules provides as follows: -"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation. On the basis of information on record and considering the submissions made by the interested parties, the Authority provisionally holds that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and those imported from the subject countries. The two are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff

classifications of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers use the two interchangeably. The Authority provisionally holds that the products manufactured by the Applicants constitute like article to the subject goods being imported into India from the subject countries.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

11. Rule 2 (b) of the AD rules defines the domestic industry as under:

“(b) domestic industry means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

12. The application has been filed by M/s Essar Steel India Limited and M/s. JSW Steel Coated Products Limited. The production of these aforesaid producers accounts for a major proportion of the total domestic production and is more than 50% of Indian production.

Submissions made by various interested parties

13. The calculation of the support to the Petition by Indian producers and the standing are not clear and the document relied upon for these calculations should be provided to the interested parties.

Examination by the Authority

14. With regard to the issue that calculation of the support to petition and standing is not clear, the Authority notes that the application has been filed by M/s. Essar Steel India Limited and M/s. JSW Steel Coated Products Limited and these producers accounts for a major proportion of the total domestic production. The share of these producers is more than 50% of Indian production as can be seen from the table below. Further, there are no supporters in the present application.

Production	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	April 15- Dec 15 (A)	POI (July 15- Dec 15)	POI (A)
Petitioners							
-Essar Steel India Ltd.	MT	179,284	200,914	140,056	169,537	79,073	158,146
-JSW Steel Coated Products Ltd.	MT	234,715	373,875	417,440	421,848	197,345	394,689
Petitioners Total Production	MT	413,999	574,789	557,496	591,385	276,418	552,835
Other producers	MT	408,001	305,211	350,504	320,615	161,582	323,165
Total Domestic production (based upon JPC data)	MT	822,000	880,000	908,000	912,000	438,000	876,000

15. Therefore, the Authority holds that the applicants command a major proportion of the production of the subject goods in India and for the purpose of this investigation the applicants satisfy the standing requirement in terms of Rule 5(3) and constitute the domestic industry in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

D. MISCELLANEOUS ISSUES RAISED BY INTERESTED PARTIES

16. The miscellaneous submissions made by various interested parties and considered relevant by the Authority are as follows:

- (i) The POI “should be representative and as recent as possible”. Deviations from the benchmarking one-year POI shall be substantiated by the Petitioners and the Designated Authority by positive evidence which is not present in the current case. The POI of six months is too short for arriving at a conclusion and it should be at least one year.
- (ii) The information submitted in the Petition is not sufficient to initiate the investigation and certain data is wrongfully treated in confidential. The non-confidential summaries of confidential information are not detailed enough.
- (iii) The domestic industry has already received multiple protection in violation of the WTO Agreements:
 - Increase of customs duty
 - Minimum import price
 - Anti-dumping investigations on other steel products.
- (iv) The import data should be provided to the interested parties in MS Excel format.
- (v) Imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods would accrue undue advantage to Domestic Industry and not in larger interest of Indian industry.

17. The miscellaneous submissions made by the Domestic Industry and considered relevant by the Authority are as follows:

- (i) Section 9A (3) of the Act is with reference to history of dumping of the product. The Petitioners request the Authority to recommend retrospective levy of anti-dumping duty on the subject goods because the conditions for retrospective levy of antidumping duty are fully satisfied.
- (ii) There is evidence of dumping of subject goods which is evident from the fact that many countries have initiated anti-dumping investigation against import of the subject goods. Massive dumping of PUC into India has taken place in a relatively short period of time causing injury to the domestic industry.
- (iii) Exporters are well aware that they are resorting to dumping which is causing injury to the domestic industry since import prices of PUC have reduced significantly as evident from the landed values for respective countries.

Examination by the Authority

18. Miscellaneous submissions made by the interested parties and considered relevant by the authority are examined and addressed as follows:

- (i) With regard to the contention of the interested parties that period of investigation should be more than 6 months, the Authority notes that according to recommendation of committee on anti-dumping practices (WTO document no. G/ADP/6 dated 16 May 2000):

“...the period of data collection for dumping investigations normally should be twelve months, and in any case no less than six months, ending as close to the date of initiation as is practicable”

Therefore, in view of above recommendation, 6 months period can be taken as the POI. The Authority has taken six months POI in other investigations also in the past.

- (ii) With regard to issue that domestic industry has already received multiple protection in violation of the WTO Agreements, the Authority notes that it is only required to examine the situation as prescribed under AD rules. Further, there is no violation of WTO Agreements by increase in customs duty. Applicability of antidumping duty on other steel products does not mean that domestic industry is not suffering injury for PUC.

- (iii) MIP was introduced by Government of India in view of low prices offered by exporters from subject countries. It is pertinent to note that MIP is in force till 4th December 2016. Once MIP expires, the domestic industry would be left without any protection from the dumped imports. Further, existence of MIP does not mean that dumping is not taking place.

- (iv) With regard to issue of import data should be provided in MS-excel format, authority notes that import data relied upon by the applicants is provided in non-confidential version of application. There is no requirement to provide the import data in MS-Excel format under the AD Rules.

- (v) The Authority notes that the argument that imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods would accrue undue advantage to Domestic Industry is presumptuous and pre-mature. Anti-dumping investigations are based on facts and law to analyze and assess the magnitude of dumping and consequent injurious effect on the domestic industry and to recommend imposition of suitable and adequate antidumping measure to provide a fair and level playing field to the domestic industry vis-à-vis dumping.

- (vi) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of a public file.

- (vii) As regards the request for retrospective imposition of anti-dumping duty, Section 9A(3) of Customs Tariff Act provides as follows:

If the Central Government, in respect of the dumped article under inquiry, is of the opinion that

(i) *there is a history of dumping which caused injury or that the importer was, or should have been, aware that the exporter practices dumping and that such dumping would cause injury; and*

(ii) *the injury is caused by massive dumping of an article imported in a relatively short time which in the light of the timing and the volume of imported article dumped and other circumstances is likely to seriously undermine the remedial effect of the anti-dumping duty liable to be levied,*

the Central Government may, by notification in the Official Gazette, levy anti-dumping duty retrospectively from a date prior to the date of imposition of anti-dumping duty under sub-section (2) but not beyond ninety days from the date of notification under that sub-section, and notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, such duty shall be payable at such rate and from such date as may be specified in the notification.

(viii) The Authority would examine the matter concerning retrospective imposition of anti-dumping duty at the stage of the final finding.

(ix) The present investigation has been initiated on the basis of prima facie analysis of the information/data furnished by the applicant showing dumping of subject goods from the subject countries, injury to the applicant on account of the said dumping and causal link between the two. The contention of the opposing interested parties that the initiation of investigation is bad in law due to misleading data furnished by the applicant and improper evaluation of data by the Authority, the Authority notes that it has prima facie satisfied itself about the accuracy and adequacy of information on the basis of information furnished by the applicants at the time of initiation.

E. DUMPING MARGIN

Market Economy Treatment (MET), Normal Value, Export Price and Dumping Margin

NORMAL VALUE

19. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

(i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

(a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Provisions relating to Non- Market Economy countries

20. Annexure-I to AD rules states as under:

7. *In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*

8. (1) *The term “non-market economy country” means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3)*

(2) *There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a nonmarket economy country*

Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3)

(3) *The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:*

(a) *the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and*

investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and

(d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph”.

Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties

21. Various submissions made by the interested parties with regard to MET, Normal value, export price and dumping margin and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

- (i) The construction of the normal value is not appropriate. The cost of production used to construct the normal value is very high due to the low capacity utilization.
- (ii) The construction of the normal value based on the domestic industry's data is not supported by enough evidence. In addition, an average dumping calculation based on the constructed normal value is too simplistic and does not reflect the different types of products.

Submissions made by the Domestic Industry

22. Various submissions made by the domestic industry with regard to MET, Normal value, export price and dumping margin during the course of the investigation and considered relevant by the Authority are as follows:

- (i) None of the Chinese producers can satisfy market economy status. None of the WTO Member countries has granted market economy status to Chinese producers on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria.
- (ii) Unless the responding Chinese exporters conform to the standards laid down under the Rules, the Designated Authority is required to determine the normal value in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Rules.
- (iii) None of the producers/exporters from China PR has claimed market economy treatment.

Examination by the Authority**Market Economy claims for Chinese producers**

23. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules.
24. As per Paragraph 8, Annexure I to the AD Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provides information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and prove to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether: -
- (i) The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values.
 - (ii) The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts.
 - (iii) Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms.
 - (iv) The exchange rate conversions are carried out at the market rate.

25. It is noted that none of producers of subject goods in China PR have claimed market economy treatment. Accordingly, the authority is not required to examine any of the above criteria and holds that producers/exporters from China PR are not operating under market economy conditions.

Determination of Normal Value for China PR

26. The Authority sent questionnaires to the known exporters/producers from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following parties have filed exporter questionnaire responses:
- (i) Shandong Hwafone Steel Co. Ltd, China PR (Producer)
 - (ii) Jiangsu Shagang International Trade Co. Ltd, China PR (Exporter)
 - (iii) Zhnagjiagang Shajing Heavy Plate Co. Ltd, China PR (Producer)
 - (iv) Shagang International Singapore Pte Ltd, China PR (Exporter)
 - (v) Qingdao RHT Steel Co. Ltd, China PR (Exporter)
 - (vi) M/s Jiangyin Xingcheng Special Steel Works, Co. Ltd, China PR (Producer/Exporter)
27. It is noted that none of producers of subject goods in China PR has claimed market economy treatment. Therefore, in view of the facts placed on record by the domestic industry for the

purpose of the provisional findings, the Authority has adopted the constructed normal value for determination of the normal value in terms of Para-7 to Annexure-1 to the Rules.

Methodology for determination of normal value

28. In view of the above, the normal value for China PR is required to be determined as per the procedure described in Para 7 of the Annexure I to the Anti-dumping Rules. As per the provisions of Para 7 of Annexure I, the normal value in China PR is required to be determined based on domestic selling prices in a market economy third country, or the constructed value in a market economy third country, or the export prices from such a third country to any other country, including India. However, if the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted to include reasonable profit margin.
29. In the absence of any reliable price and cost details for the subject goods in any market economy third country, the Designated Authority has constructed the normal value for China PR on the basis of price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin. Accordingly, the Normal Value for all the exporters from China PR has been provisionally determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Determination of Normal Value for producers and exporters in European Union

30. The Authority notes that no producer/exporter from the European Union has responded to and cooperated with the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in the EU, the Authority has determined provisional weighted average normal value at ex-factory level for subject goods on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

EXPORT PRICE

M/s. Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd, China PR (Producer) through related traders M/s. Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd, China PR and M/s Shagang International (Singapore) Pte. Ltd, Singapore

31. From the response filed by M/s. Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd, China PR (“Shajing”), the Authority notes that Shajing is the producer of the subject goods. Its related company, M/s Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd (“Shagang International”) has exported the subject goods to India through another related trading company M/s Shagang International (Singapore) Pte. Ltd. (“Shagang SG”).
32. From the response submitted by Shagang SG, the Authority notes that Shagang SG has further resold the subject goods to Samsung C and T Corporation, Korea (“Samsung”). Samsung has not filed any response. Further, Shajing has not reported any exports to India in Appendix-2. In the absence of information in Appendix-2 from the producer, it is not possible to ascertain the ex-factory export price to India.

33. Therefore, in view of absence of complete information from Shajing including non-cooperation by Samsung, the Authority does not accept the response filed by Shajing for the purpose of provisional findings. Accordingly, the export price for Shajing is based on the facts available with the Authority.

Shandong Hwafone Steel Sheet Co., Ltd. (Producer) through unrelated trader M/s. Qingdao RHT Steel Co., LTD.

34. From the response filed by M/s Shandong Hwafone Steel Sheet Co., Ltd, China PR (“Hwafone”), the Authority notes that Hwafone is the producer of the subject goods and has exported the subject goods through unrelated trader M/s Qingdao RHT Steel Co., Ltd (“RHT”). The Authority notes that Hwafone has not reported any exports to India in Appendix-2. In the absence of information in Appendix-2 from the producer, it is not possible to ascertain the ex-factory export price to India.
35. Therefore, in view of absence of complete information from Hwafone, the Authority does not accept the response filed by Hwafone for the purpose of the provisional findings. Accordingly, the export price for Hwafone is based on the facts available with the Authority.

M/s Jiangyin Xingcheng Special Steel Works, Co., Ltd (Producer/Exporter)

36. From the response filed by M/s Jiangyin Xingcheng Special Steel Works, Co., Ltd, China PR (“JXSS”), the Authority notes that JXSS has exported plates having thickness more than 6mm and same are not covered under the scope of the PUC. Therefore, no examination is done for information submitted by JXSS.

Export Price for non-cooperating producers and exporters from China PR

37. The Authority notes that no other producer/exporter from China PR has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in China PR, including the above mentioned producers/exporters whose responses have not been accepted by the Authority, the Authority has determined the provisional weighted average export price for subject goods on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price for producers and exporters in European Union

38. The Authority notes that no producer/exporter from EU has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in EU, the Authority has determined the provisional weighted average export price for subject goods on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

DUMPING MARGIN

39. The export price to India (net of all the adjustments) has been compared with the normal value to determine the dumping margin. The provisional dumping margin during the POI for all the exporters/producers from the subject countries has been determined as shown in the Dumping Margin table below.

Dumping Margin Table

S. No	Country	Producer	Exporter	Normal Value (USD/MT)	Net Export Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range %
1.	China PR	All	All	***	***	***	***	50-60
2.	European Union	All	All	***	***	***	***	70-80

40. It is seen that the dumping margins are quite significant and more than the limits prescribed under the Rules in respect of exports made by all the producers-exporters of the product under consideration from subject countries.

F. INJURY

Submissions made by exporters, importers and users

41. The submissions made by the opposing interested parties with regard to injury related issues and considered relevant by the authority are as follows:
- The Petition does not contain adequate and sufficient evidence of dumping and injury.
 - The performance of the domestic industry has been stable and has improved. There is no change in the landed value, price undercutting has declined, production of the domestic industry and capacity utilization has increased.
 - The injury is caused by the adverse export performance of the domestic industry. The injury has been caused by factors other than imports from China PR.
 - The demand for retroactive measures is unwarranted.
 - The methodology used to determine the non-injurious price needs to be revised. The DGAD should not give 22% ROCE. The CESTAT has given decision that 22% ROCE is not appropriate. In addition, none of the steel producers has ever attained 22% ROCE.
 - The cumulation is not appropriate in the light of the conditions of competition given that the Chinese imports account for 84% of the total imports.
 - The domestic industry does not suffer injury given that most of the economic parameters either show a positive trend or are largely stable. The production, demand, sales, capacity and capacity utilization have increased.
 - The domestic industry is loss making but it was already loss making in 2012-13 at the beginning of the period considered for the injury determination.
 - The injury has been caused by other factors that the authority is required to examine.
 - The domestic industry has not been making profit since the beginning of the period considered for the injury determination. Petitioners were already making losses in 2012-13.
 - Performance of the domestic industry which has a problem of efficiency with utilization rate fluctuating around 50%. The decision to invest and increase the production capacity has caused the injury.

Submissions made by the Domestic Industry

42. The following are the submissions with regard to injury related issues made by the domestic industry and considered relevant by the Authority:

- (i) Imports of the subject goods have increased in absolute terms over the entire period of investigation. Imports of the PUC from the subject countries have increased in absolute terms.
- (ii) Imports of the subject goods have increased relative to production and also relative to consumption in India.
- (iii) Market share of the Domestic Industry has decreased even though demand for the subject goods has been rising in India. This is due to the reason that imports have aggressively captured the increase in demand and the market share of imports from subject countries sharply increased from 2012-13 to POI (A).
- (iv) The Domestic Industry has not been able to increase its production and sales commensurate with the increase in demand.
- (v) Inventories of the Domestic Industry have been on the rise as the Domestic Industry has not been able to increase its sales despite increase in demand. Imports have been aggressively capturing the demand in India.
- (vi) There is significant price depression and suppression due to low priced dumped imports coming into India.
- (vii) The Domestic Industry's profitability has been drastically affected. The profitability has followed a negative trend during the entire injury period and the losses have further aggravated during the POI.
- (viii) The export performance of the Domestic Industry in no way has affected its financial and economic situation. Also, the petitioners have ignored the information related to exports while examining the injury parameters and entire injury analysis is based only on domestic performance of Applicants.
- (ix) The analysis overwhelmingly indicates that the Domestic Industry is suffering material injury due to increasing dumped imports of PUC into India. There exists a strong nexus between the increase in dumped imports of the subject goods and the material injury being suffered by the Domestic Industry.
- (x) Interested parties have submitted that injury being suffered by the domestic industry is due to other factor and over capacities. These claims are very general and without any facts and figures to support. The fact that injury has been caused due to dumped imports of the subject goods in India has already been established. The domestic industry has been in existence since many years and has been doing well in the past.

Examination by the Authority

43. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigation with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as below:
- (i) The Authority notes that landed value of imports of the subject goods from the subject countries has declined and the domestic industry has been forced to match such low prices causing material injury to domestic industry.
 - (ii) With regard to the export performance of the domestic industry, the authority notes that the entire injury analysis is based only on the domestic performance of the DI.
 - (iii) The Authority has further analysed the contention of the interested parties that injury being suffered by the domestic industry is due to other factors. These claims are very general and without any facts and figures to support. The fact that injury has been caused due to the dumped imports of the subject goods in India has been established in the succeeding paragraphs. Infrastructure and capacities are in place with the domestic industry to meet the demand of the subject goods.
 - (iv) With regard to the issue of allowing 22% ROCE, authority notes that it is consistent practice of the authority to give 22% ROCE.

Cumulative Assessment

44. Article 3.3 of WTO agreement and Annexure II para (iii) of the Anti-dumping Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- (i) The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
 - (ii) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
45. The Authority notes that:
- (i) The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules.
 - (ii) The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
 - (iii) Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by

each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

46. In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from exports of the subject goods from the subject countries.
47. Rule 11 of AD Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the AD Rules.

Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry

Assessment of Demand

48. The demand/apparent consumption of the subject goods has been determined by adding domestic sales of Indian producers of like product and imports of the subject goods from all the countries. For the purpose of present injury analysis, the Authority has relied upon the import data procured from CBEC. The Authority notes that demand/apparent consumption of the subject goods increased significantly over the injury period as can be seen in the table below:

Particulars (in MT)	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015- Dec 2015 (A)	POI (Jul 2015- Dec 15)	POI (A)
Total dumped imports from subject countries	60,771	73,854	209,895	412,322	213,311	426,622
Imports from other countries	41	304	0	192	0	0
Total imports	60,812	74,159	209,895	412,513	213,311	426,622
Domestic sales of petitioners	230,213	327,096	308,076	415,032	190,574	381,148
Domestic sale of other producers	226,878	173,687	193,691	225,007	111,402	222,803
Total Demand/Apparent consumption	517,903	574,942	711,662	1,052,552	515,287	1,030,573

Import Volumes and Share of the Subject Countries

49. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume effect of dumped imports of the subject goods from the subject countries is analyzed as under:

Particulars (in MT)	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015- Dec 2015 (A)	POI (Jul 2015- Dec 15)	POI (A)
Dumped imports from subject countries	60,771	73,854	209,895	412,322	213,311	426,622
Trend	100	122	345	678	351	702
Imports from other countries	41	304	0	192	0	0
Trend	100	748	-	471	-	-
Total Imports	60,812	74,159	209,895	412,513	213,311	426,622
Trend	100	122	345	678	351	702
Total Demand/Apparent consumption	517,903	574,942	711,662	1,052,552	515,287	1,030,573
Trend	100	111	137	203	99	199
Dumped imports from Subject Countries relative to consumption	11.73%	12.85%	29.49%	39.17%	41.40%	41.40%
Production of Petitioners	413,999	574,789	557,496	591,385	276,418	552,835
Dumped imports from Subject Countries relative to petitioners' total production	14.68%	12.85%	37.65%	69.72%	77.17%	77.17%

50. The authority notes as under from the above table:

- (i) Imports of subject goods from subject countries have increased in absolute terms from 60,771 MT in 2012-13 to 426,622 MT in POI (A).
- (ii) Imports of subject goods from subject countries have increased in relation to petitioners' production from 14.68 % in 2012-13 to 77.17 % in POI (A).
- (iii) Imports of the subject goods from the subject countries have increased in relation to consumption in India from 11.73% in 2012-13 to 41.4% in POI (A).

51. It is, thus, concluded that imports of the PUC from the subject countries have increased both in absolute terms and in relation to production and consumption in India.

Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

52. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

53. It has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

Price Undercutting

54. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level. The domestic prices and margin of undercutting is shown as per the table below:

Price Undercutting	July 15 to Dec 15	China PR	EU
Landed Value	Rs. /MT	***	***
Domestic Selling Price	Rs. /MT	***	***
Price Undercutting	Rs. /MT	***	***
Price Undercutting	%	***	***
Price Undercutting Range	%	20-30%	35-45%

55. The Authority notes from the aforesaid table that significant price undercutting exists for China PR as well as European Union. Due to such significant price undercutting, the domestic industry is unable to increase their selling prices so as to recover their cost and earn a reasonable rate of return. If the Domestic Industry does not respond to imports by bringing down its prices, it will lose more customers and the injury would be more severe.

Price Underselling

56. The Authority has also examined the price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject countries. For this purpose, the NIP determined for the domestic industry has been compared with the landed price of imports. Comparison of weighted average NIP of the domestic industry with weighted average landed price of imports shows as follows:

Price Underselling	July 15 to Dec 15	China PR	EU
Landed Value	Rs. /MT	***	***
NIP	Rs. /MT	***	***
Injury Margin	Rs. /MT	***	***
Injury Margin	% of L.V	***	***
Injury Margin Range		30-40%	50-60%

57. It is seen that the landed price of the subject goods from the subject countries was significantly lower than the NIP determined for the domestic industry.

Price Suppression/Depression

58. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown in the table below:

Particulars (Rs. per MT)	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015- Dec 2015	POI (July 2015- Dec 15)
Cost to make and sell	***	***	***	***	***
Trend	100	104	106	95	94
Domestic Selling Price	***	***	***	***	***
Trend	100	104	105	93	91
Landed Value	***	***	***	***	***
Trend	100	109	109	100	97

59. It is noted that decline in the domestic selling price is higher than the decline in the cost of sales. The import prices have remained significantly lower than the domestic selling prices as well as the cost to make and sell for domestic industry throughout the injury investigation period. The low priced dumped imports did not allow the domestic industry to fetch a selling price which could recover even its cost. The imports were thus suppressing the prices of the domestic industry in the market.

Economic parameters of the domestic industry

60. Annexure II to the AD Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of the performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

Production, Capacity Utilization and Sales

61. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization was as follows:

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015-Dec 2015 (A)	POI (Jul 2015- Dec 15)	POI (A)
Installed Capacity (MT)	868,000	1,093,000	1,093,000	1,093,000	546,500	1,093,000
Total production (MT)	413,999	574,789	557,496	591,385	276,418	552,835
Capacity Utilization	47.70%	52.59%	51.01%	54.11%	50.58%	50.58%
Domestic Sales	230,213	327,096	308,076	415,032	190,574	381,148

62. The Authority notes that even though the domestic production of the subject goods have increased, the significant increase in dumped imports has not allowed the domestic industry to achieve optimum capacity utilisation during injury investigation period.

Profitability

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015-Dec 2015 (A)	POI (Jul 2015- Dec 15)	POI (A)
Profit (Rs. In crores)	***	***	***	***	***	***
Trend	(100)	(150)	(166)	(253)	(127)	(254)
Profit (Rs./MT)	***	***	***	***	***	***
Trend	(100)	(106)	(124)	(140)	(153)	(153)
Cash Profits (Rs. crores)	***	***	***	***	***	***
Trend	(100)	(133)	(174)	(282)	(144)	(287)
Cash Profit (Rs./MT)	***	***	***	***	***	***
Trend	(100)	(94)	(130)	(156)	(174)	(174)

63. The Authority notes the following from the above table:

- (i) The domestic industry's profitability has been adversely affected due to increased dumping by exporters from subject countries. The losses suffered by the domestic industry have significantly increased during POI.
- (ii) Due to severe dumping from subject countries during POI, domestic industry has not been able to recover its cost of sales leave aside earning a reasonable profit.

- (iii) It is, therefore, concluded that the dumped imports have severely affected the profitability of the domestic industry.

Market Share

64. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below:

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015- Dec 2015 (A)	POI (Jul 2015- Dec 15)	POI (A)
Demand (MT)	517,903	574,942	711,662	1,052,552	515,287	1,030,573
Indexed	100	111	137	203	99	199
Market Share						
Share of Petitioners	44.45%	56.89%	43.29%	39.43%	36.98%	36.98%
Share of all other Producers	43.81%	30.21%	27.22%	21.38%	21.62%	21.62%
Share of Subject countries	11.73%	12.85%	29.49%	39.17%	41.40%	41.40%
Share of Other countries	0.01%	0.05%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%

65. From above table, the Authority observes that the market share of the Domestic Industry has decreased even though demand for the subject goods has been rising in India. Further, the authority notes that market share of the imports from the subject countries has increased over the injury period. This is due to the reason that imports have aggressively captured the increase in demand.
66. The domestic industry has not been able to increase the sales of the PUC commensurate with the increase in demand because of the significant volume of dumped imports coming from the subject countries.

Inventories

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15	POI (Jul 2015- Dec 15)
Average Inventory (MT)	***	***	***	***
Trend (Indexed)	100	136	141	229

67. The Authority notes that the Domestic Industry is facing significant accumulated inventories. The levels of inventories have been increasing as compared to the base year. Due to increasing imports, the market share of the Domestic Industry has come down and the increased demand has been significantly captured by imports. As a result, the Domestic Industry is unable to increase its production and sales which is leading to a situation of inventory accumulation over the injury period.

Growth

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	POI(A)
Cost of Production	%	4%	2%	-11%
Selling Price	%	4%	1%	-13%
Loss	%	50%	11%	53%
Cash Loss	%	33%	31%	65%
Market Share	%	12%	-24%	-16%

68. The Authority notes that the growth of the domestic industry with regard to profitability, market share and selling price has been negative.

Ability to raise capital investments

69. The Authority notes that given the rising demand of the product in India, the domestic industry has made significant investments in plant and machinery. However, despite these investments, the performance of the domestic industry has deteriorated considerably and further investment may get adversely affected.

Level of dumping & dumping margin

70. It is noted that the imports from the subject countries are entering the Indian market at dumped prices and that the margins of dumping are significant.

Factors Affecting Domestic Prices

71. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of the imported material from the subject countries is below the non-injurious price of the domestic industry, causing significant price under selling in the Indian market. Thus, the factor affecting the domestic prices is landed value of the subject goods from the subject countries.

Conclusion on injury

72. It is thus seen that there has been a significant increase in the volume of dumped imports from the subject countries in absolute terms. The imports have increased significantly in relation to consumption and production of the product in India. Dumped imports have had significant adverse price effect in terms of price suppression and depression. Effect of dumped imports has been to reduce the domestic prices of the subject goods. Low priced dumped imports have forced the domestic industry to fetch a market price which could not even cover its cost. The domestic industry is suffering significant price undercutting and underselling. There exists price depression and suppression due to low priced dumped imports coming in India. The dumping margin determined by the Authority is quite significant. With regard to consequent impact of dumped imports on the domestic industry, it is noted that dumped imports from the subject countries have adversely impacted the performance of the domestic industry in respect of capacity utilization, inventories, market share, profits and cash profits. Inventories with the domestic industry increased. The profitability of the domestic industry has been drastically affected. This is evident from the fact that the losses suffered by the domestic industry have significantly increased during POI. Thus, the Authority provisionally concludes that the domestic industry has suffered material injury.

Causal Link

73. The Authority has examined whether other factors listed under the Anti-dumping Rules could have contributed to injury to the domestic industry. The examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry has been done as follows:

Imports from third countries

74. The imports from countries other than the subject countries are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the domestic industry.

Contraction in demand

75. The demand for the subject goods has shown an increasing trend. Accordingly, fall in demand cannot be the reason for injury to the domestic industry. In fact, the domestic industry has not been able to increase its sale and market share commensurate to increase in demand.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

76. The Authority notes that there is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

Developments in technology

77. The technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor causing injury to the domestic injury.

Changes in pattern of consumption

78. The domestic industry is producing the type of goods that have been imported into India. Possible changes in the pattern of consumption are not a factor that could have caused injury to the domestic industry.

Export performance

79. Claimed injury to the domestic industry is not on account of possible significant deterioration in export performance of the domestic industry. In any case, the authority has considered domestic performance only for assessing injury to domestic industry wherever possible.

Performance of the domestic industry with respect to other products

80. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

Productivity of the domestic industry

81. The Authority notes that the deterioration in productivity has not caused injury to the domestic industry.

Factors establishing causal link

82. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated due to dumped imports from the subject countries. Causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

- Imports of the subject goods from the subject countries have increased in absolute terms over the entire period of investigation.
- Imports of the subject goods from the subject countries have increased relative to production and consumption in India.
- Market share of the Domestic Industry has decreased even though demand for the subject goods has been rising in India. This is due to the reason that imports have aggressively captured the increase in demand.
- Inventories of the Domestic Industry have been on the rise as the Domestic Industry has not been able to increase its sales despite increase in demand. Imports have been aggressively capturing the demand in India.
- There exists price suppression and price depression due to low priced dumped imports coming in to India.
- The Domestic Industry's profitability has been drastically affected. This is evident from the fact that the losses suffered by the domestic industry have significantly increased during the POI.

83. The above analysis indicates that the Domestic Industry is suffering material injury due to increasing dumped imports of the PUC into India. There exists a strong nexus between the increase in dumped imports of the subject goods from the subject countries and the material injury being suffered by the Domestic Industry.

Conclusion on Injury and Causation

84. From the above examination of injury and causal link, the Authority provisionally concludes that the domestic industry has suffered injury as a result of dumping of the subject goods from the subject countries. There has been a significant increase in the volume of dumped imports from the subject countries in absolute terms throughout the injury period and in relation to production and consumption in India. The dumped imports have had significant adverse effect on the prices of the domestic industry in the market. The dumping margin for the subject countries has been determined and is considered significant. Dumped imports from the subject countries have adversely impacted production, sales and capacity utilization. Market share of the domestic industry has significantly declined whereas that of subject imports has significantly increased. Performance of the domestic industry has significantly deteriorated in respect of profits, cash profits and returns. Inventories have increased. The Authority thus provisionally concludes that the domestic industry has suffered material injury as a result of dumped imports from the subject countries.

85. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry and compared with the landed values of the subject imports from the subject countries to determine the injury margin. The provisional injury margins have been determined as follows:

Injury Margin

S.No	Countries	Producer	Exporter	NIP (USD/MT)	Landed Value (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin %	Injury Margin Range %
1.	China PR	All	All	***	***	***	***	30-40

2.	EU	All	All	***	***	***	***	50-60
----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

86. The level of dumping margins and injury margins as determined are considered significant.

G. Indian industry's interest & other issues

87. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the countries. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

88. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these product. The domestic industry submitted that imposition of proposed duty shall have insignificant cost implications for the consumer. Therefore, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

H. Recommendations

89. After examining the submissions made and issues raised, and considering the facts available on record, the Authority provisionally concludes that:

- (i) The product under consideration has been exported to India from the subject countries below normal value.
- (ii) The domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from the subject countries.
- (iii) The injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries.

90. The Authority notes that the investigation was initiated and it was notified to all interested parties. Adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the Anti-Dumping Rules and having established a positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of provisional anti-dumping duty is necessary to offset dumping and injury.

91. Having regard to the lesser duty rule and imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, as the difference between the landed value of the subject goods and the amount indicated in Col 8 of the duty table appended below, provided the landed value is less than the value indicated in Col 8. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the

customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

Sl. No.	Heading/ Sub-heading	Description of Goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	7210, 7212, 7225 and 7226	Pre-painted, painted, colour coated or organic coated flat steels in coils or not in coils whether or not with metallic coated substrate of zinc, aluminium-zinc or any other substrate coating	China PR	China PR	Any	Any	849	MT	US\$
2.	- do -	- do -	China PR	Any country other than the subject countries	Any	Any	849	MT	US\$
3.	- do -	- do -	Any country other than the subject countries	China PR	Any	Any	849	MT	US\$
4.	-do-	-do-	European Union	European Union	Any	Any	849	MT	US\$
5.	-do-	-do-	European Union	Any country other than the subject countries	Any	Any	849	MT	US\$
6.	-do-	-do-	Any country other than the subject countries	European Union	Any	Any	849	MT	US\$

I. FURTHER PROCEDURE

92. The procedure as below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:-

- (i) The Authority invites comments on these provisional findings from all the interested parties and the same, considered relevant by the Authority, would be considered in the final findings;
- (ii) Exporters, importers, the applicants and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views known, within forty days from the date of the publication of these preliminary findings. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings.
- (iii) The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary.
- (iv) The Authority would disclose the essential facts as per the Anti-dumping Rules before announcing the final findings.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority